● वर्ष-3
● अंक-168
रायपुर, गुरुवार
22 फरवरी 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› डर्माटोमायोसिटिसः जानिए क्या ...

वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम विभाग की अनुदान मांगें पारित

प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 2024-29 बनेगी

प्रवासी श्रमिकों के लिए मोर चिन्हारी भवन

रायपुर। वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के विभागों से संबंधित 773 करोड़ 28 लाख 42 हजार रूपए की अनुदान मांगें विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दी गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने अनुदान मांगों पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में प्रवास करने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए वहां ''मोर चिन्हारी भवन'' की स्थापना की जाएगी। इसके पहले चरण में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र में जहां राज्य के श्रमिक अधिक संख्या में प्रवास करते हैं, मोर चिन्हारी भवन बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को समय-समय पर सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने सदन में बताया कि प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक नीति 31 अक्टूबर 2024 तक प्रचलन में है। राज्य की आवश्यकता के अनुरूप इसकी समीक्षा कर नई औद्योगिक नीति 2024-2029 जारी की जाएगी। नई नीति में राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पादों, वनोपजों, खनिज सम्पदा एवं रोजगारमूलक उद्योगों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए नये उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के लिए सभी हितधारकों के साथ बात करके तथा अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर एक श्रेष्ठ नीति बनाएंगे, ताकि औद्योगिक विकास में तेजी आए और प्रदेश में रोजगार के नये अवसर सृजित हो सके। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री देवांगन ने सदन में बताया कि नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 60 करोड़ रूपए, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने पृथक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रूपए, लागत पूंजी अनुदान के लिए 200 करोड़ रूपए एवं ब्याज अनुदान के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान नए बजट में किया गया है। उन्होंने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। साथ ही प्रदेश में अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट के क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए प्रारंभिक कार्ययोजना तैयार करने के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। श्री देवांगन ने सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोरबा जिले में एल्यूमिनियम पार्क की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के लिए आगामी बजट में आरंभिक तौर पर 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वन संसाधनों से परिपूर्ण बस्तर और सरगुजा संभाग में लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान के लिए 13 करोड़ रूपए की राशि प्रावधानित है। उन्होंने बताया कि युवाओं में स्टार्ट-अप, इनोवेशन एवं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में सेंट्रल इन्स्टूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सदन में बताया कि पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट निजी शालाओं में निःशुल्क पढ़ाने के लिए शीघ्र नई योजना प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों के द्वारा आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक से लिए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज में अनुदान देने की भी योजना जल्दी शुरू की जाएगी। इससे श्रमिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे और वे स्वयं मालिक बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने सदन में कहा कि राज्य में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु सड़क, पानी, बिजली इत्यादि के संधारण एवं नवीन परियोजनाओं के साथ ही नवा रायपुर में आईटी आधारित ''प्लग एवं प्ले'' मॉडल का विकास किया जाएगा।

असंगठित श्रमिकों के लिए 123 करोड़ 98 लाख

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के तहत अधिसूचित 56 प्रवर्ग के 17 लाख 54 हजार पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु आगामी बजट में 123 करोड़ 98 लाख रूपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक स्थान में प्राप्त हो सके, इसके लिए शासन द्वारा श्रमेव जयते वेबपोर्टल बनाया जा रहा है। इसके लिए बजट में 2 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

सन्निर्माण कर्मकारी को 505 करोड़

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 505 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का व्यय प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्र के संगठित श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार

इस योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 5 रूपए में गरम भोजन, दाल, चावल, सब्जी, अचार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के तहत सात जिलों रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुन्द और सूरजपुर में 21 केन्द्र संचालित हो रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से प्रतिदिन करीब 3200 श्रमिकों को गरम भोजन मिल रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 9 जिलों में 24 नये केन्द्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि नये बजट में श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के लिए 32 करोड़ रूपए और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 6 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत श्रमिकों के लिए 61 करोड़ रूपए प्रावधानित है।

नगर निगम के बजट में महापौर की घोषणा

रायपुर में शुरू होगा लाईट मेट्रो ट्रेन

रायपुर। नगर निगम रायपुर में अपने कार्यकाल का अंतिम बजट महापौर एजाज ढेबर ने बुधवार को निगम मुख्यालय में पेश किया। पेश किए गए बजट 1901 करोड़ 31 लाख 93 हजार रुपयों को फायदे वाला बताते हुए निगम को 57 लाख 71 हजार रुपये का लाभ होने वाला बजट बताया है। महापौर ने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गतिशील बनाने के लिए मेट्रो लाइट ट्रेन परियोजना की घोषणा करते हुए कहा कि इस परियोजना पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इस परियोजना को पीपीपी मोड के माध्यम से पूरा किए जाने का प्रस्ताव बजट में रखा। महापौर ने बजट को युवा और महिलाओं पर केंद्रित करार दिया है।

विकासों की सौगात देते हुए पेश बजट में महापौर ने शहर के विकास, प्रदूषण कम करने का पुख्ता इंतजाम तथा शहर में कला और संस्कृति को एक नया आयाम देने जैसी घोषणाएं की है। साथ ही शहर में बढ़ रहे आवारा कुत्तों के गैंग को लेकर प्रत्येक जोन में डॉग स्कैचर उपलब्ध कराने का प्रावधान करते हुए बजट में 10.15 करोड़ की लागत से वर्ल्ड स्किल सेंटर खोलने की

57 लाख 71 हजार के लाभ वाला निगम का बजट पेश

घोषणा भी की जिसमें कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। बजट पेश करने से पूर्व महापौर एजाज ढेबर बजट ब्रीफकेस लेकर आकाशवाणी स्थित काली मंदिर में देवी का दर्शन कर आर्शीवाद लिया और सीधे नगर निगम मुख्यालय पहुंचे जहां अपना आखिरी बजट आमसभा में पेश किया।

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 10.15 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड स्किल सेंटर तैयार किया जाएगा इसके अंतर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही साथ रोजगार मूलक कार्यक्रमों से उन्हें जोड़ा जाएगा। युवाओं को उनकी नैसर्गिक प्रतिभा के अनुरूप रोजगार के अवसर मिले, योग्यता के अनुरूप काम मिले और अर्जित कौशल से वे सम्मान के साथ अपने करियर का चयन कर सकें यह सुविधा प्रदान की जाएगी। शहर में बढ़ रहे आवारा कुत्तों के रहवास के लिए 50 लाख रुपए की लागत से डॉग शेल्टर तैयार किया जाएगा। इस सेंटर में केन्द्र व राज्य सरकार के अधिनियम, नियमों व उपबंधों के अनुरूप पशु चिकित्सकों की देखरेख में यहां बीमार कुत्तों को रखने घायलों के उपचार बधियाकरण आदि की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री आवासीय परिसरों में सामुदायिक भवनों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। रहवासियों की अपेक्षा के अनुरूप सामुदायिक भवनों का निर्माण की योजना तैयार की गई है। इसके अलावा इन परिसरों के रख-रखाव हरीतिमा बढ़ाने के प्रबंध भी किए जाएंगे। नगर निगम द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से कौशल प्रशिक्षण केन्द्र सह योगा सेंटर, जिम उद्यान और खेल प्रक्षेत्र निर्धारित करते हुए व्यवसायिक परिसर तैयार करने की योजना तैयार की जा रही है।

आस्था और पौराणिक महत्व के लिए प्रतिष्ठित महादेव घाट क्षेत्र के विकास के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत इस स्थल में आगन्तुकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार व सौंदर्यीकरण कर इसे रमणीक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस हतु 5 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ की लागत से तीन मिनी स्टेडियम निर्माण की योजना है। इसके निर्माण से छोटे व मध्यम आयोजनों के लिए सभी आयु वर्ग को उपयुक्त स्थल प्राप्त होगा और रचनात्मक गतिविधियों से नई प्रतिभाएं आगे आएगी। रायपुर आगमन को विशेष पहचान देने के लिए 4 करोड़ की लागत से 7 स्थलों पर आकर्षक प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे।

राजभर ने उप्र का 3 और बिहार की दो सीटों पर ठोका दावा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होते दिखाई दे रही है। भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने भाजपा के सामने एक बड़ी डिमांड रख दी है। उन्होंने भाजपा से लोकसभा चुनाव में पांच सीटों की डिमांड की है जिनमें से तीन सीटें उत्तर प्रदेश की जबकि दो सीटें उन्होंने बिहार से मांगी है। उत्तर प्रदेश से उन्होंने सलेमपुर, घोसी और गाजीपुर की मांग रखी है।

9वें रायसीना डायलॉगः भारत से साझेदारी यूरोप की विदेश नीति का आधार होः ग्रीस प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके यूनानी समकक्ष क्यारीकोस मित्सोटाकिस ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में नौवें रायसीना संवाद में भाग लिया। रायसीना डायलॉग भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारत की बढ़ती रुचि हमारे निरंतर विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत-ग्रीस साझेदारी निश्चित

रूप से एक आधार के रूप में काम कर सकती है। 9वें रायसीना डायलॉग में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोटाकिस ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ और बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रीस ने किसी भी यूरोपीय देश की तुलना में सबसे तेज़ विकास दर हासिल की है....भारत पहले से ही ग्रीस के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रहा है, जिसमें जीएमआर द्वारा नए हवाई अड्डे का निर्माण भी शामिल है.. हमारे द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी से सहमत हैं कि हमें और अधिक करने की आवश्यकता है.

प्रमुख समाचार

शाह आज जांजगीर-चांपा से करेंगे लोस चुनावी शंखनाद

जांजगीर-चांपा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार यानी 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे. केंद्रीय गृहमंत्री जांजगीर चांपा जिले के हाईस्कूल मैदान में आमसभा को संबोधित करेंगे. जांजगीर से वे लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं. बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में यह पहला दौरा होगा. जांजगीर-चांपा जिले के हाईस्कूल मैदान में गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे, जांजगीर-चांपा जिले के हाई स्कूल ग्राउंड में अमित शाह, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, बीजेपी प्रदेश संगठन प्रभारी ओम माथुर के साथ कई मंत्री पहुंचेगे और लोक सभा चुनाव का शंखनाद करेंगे. इस बीच बुधवार को कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने प्रदेश के गृहमंत्री ओपी चौधरी जांजगीर पहुंचे. बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को कोंडागांव भी आएंगे. कल बस्तर, कांकेर और महासमुंद क्लस्टर की बैठक भी होगी. बैठक में छत्तीसगढ़ प्रभारी औम माथुर, सह प्रभरी नितिन नवीन, मंत्री केदार कश्यप, लता उसेंडी, अजय चंद्राकर सहित लोकसभा संयोजक मौजूद रहेंगे.

कांग्रेस ने आयकर विभाग पर 65 करोड़ जब्त करने के लगाए आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि आयकर विभाग ने पार्टी के विभिन्न खातों से अलोकतांत्रिक तरीके से 65 करोड़ रुपये की राशि निकाले हैं। अजय माकन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कल, आयकर विभाग ने बैंकों को कांग्रेस, आईवाईसी और एनएसयूआई खातों से 65 करोड़ रुपये से अधिक - आईवाईसी और एनएसयूआई से 5 करोड़ रुपये और कांग्रेस से 60.25 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का आदेश दिया, जो कि भाजपा सरकार का एक चिंताजनक कदम है। अजय माकन ने आगे कहा कि क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए आयकर देना आम बात है? नहीं, क्या भाजपा आयकर देती है? नहीं, फिर कांग्रेस पार्टी को 210 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व मांग का सामना क्यों करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज की आईटीएटी कार्यवाही के दौरान, हमने अपना मामला प्रस्तुत किया। सुनवाई कल भी जारी रहने वाली है। विचाराधीन धनराशि जमीनी स्तर के प्रयासों से जुटाई गई थी, जिसमें आईवाईसी और एनएसयूआई द्वारा क्राउड फंडिंग और सदस्यता अभियान शामिल थे।

मोदी काशी में देंगे 31 हजार करोड़ के विकास कार्यों का हिसाब

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले 22 फरवरी को दो दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं। 10 सालों में 31 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का हिसाब भी वो काशी की जनता को देंगे। 23 फरवरी को सीरगोवर्धन में संत रविदास मंदिर के पास मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वही क्रा॥ के स्वतंत्रता भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं और छात्रों को पुरुस्कार देंगे। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बताया कि संत रविदास के जन्मस्थली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन पूजन के बाद करीब 100 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यही पर वो संत रविदास के प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे। यहां से वो सीधे करखियांव एग्रो पार्क पहुंचेंगे। जहा 14 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं का सौगात वाराणसी और अगल बगल के जिलों को देंगे। 622 करोड़ की लागत से तैयार अमूल के प्लांट का लोकार्पण करेंगे। चार बड़े नेशनल हाइवे का लोकार्पण होगा।

उप्र में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, अन्य के खाते में 63

लखनऊ। पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हो गया है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कियह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष 63 सीटों पर सपा और अन्य दलों के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा ने कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। इस रणनीतिक गठबंधन का लक्ष्य भारत गठबंधन को मजबूत करना है, जिससे 2024 में सरकार बनाने की संभावना बढ़ जाएगी। गैर-भाजपा वोटों को एकजुट करके, गठबंधन अपनी चुनावी ताकत बढ़ाना चाहता है। सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने बातचीत की शुरुआत की और राहुल गांधी से इस मामले पर चर्चा करने के बाद अखिलेश यादव से बात की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा की आज सुबह फोन पर अखिलेश से बातचीत के बाद सीट बंटवारे पर मंडरा रहे बादल छंट गए। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को संकेत दिया कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन पटरी पर है।

कांग्रेस संग सीट शेयरिंगः देखते हैं अगले 2-3 दिन में क्या होता है

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कांग्रेस के साथ पार्टी के गठबंधन पर सवालों का जवाब दिया। जब केजरीवाल से पूछा गया कि सीट बंटवारे में देरी क्यों हुई तो उन्होंने कहा, देखते हैं 1-2 दिनों में क्या होता है। केजरीवाल की यह टिप्पणी लोकसभा से पहले दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत पर सस्पेंस के बीच आई है। आप द्वारा कांग्रेस को दिल्ली की सात लोकसभा सीटों में से केवल एक की पेशकश करने के बाद इंडिया ब्लॉक पार्टियों के बीच तनाव बढ़ गया। अरविंद केजरीवाल मे कहा, देखते हैं अगले 1-2 दिन में क्या होता है?...बहुत देरी हो गई है, जल्दी होना चाहिए। आप सांसद संदीप पाठक ने पिछले हफ्ते कहा था, योग्यता के आधार पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक भी सीट की हकदार नहीं है, लेकिन गठबंधन के धर्म को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें दिल्ली में एक सीट की पेशकश कर रहे हैं। पाठक ने दिल्ली में लोकसभा सीटों पर पार्टी की पकड़ में कमी की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया था। पाठक ने कहा, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में शून्य सीटें मिली हैं।

दीदी ने बना दी जोड़ी, अखिलेश के इन दो विकल्पों के आगे ढेर हो रही थी कांग्रेस की रणनीति

अमित शर्मा

कई झटके खाने के बाद अंततः सपा-कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है। यूपी की 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस और शेष 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के अन्य दल चुनाव लड़ेंगे। जिस समय यह माना जा रहा था कि सपा-कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटना तय हो गया है, प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से सीधी बातचीत कर पूरा मामला पलट दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता को न केवल कांग्रेस को उन सीटों को देने के लिए मना लिया, जिन्हें समाजवादी पार्टी देने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि पूर्व से पश्चिम तक प्रदेश में कांग्रेस के मजबूत होने की नींव भी रख दी।

दरअसल, कांग्रेस नेताओं की चिंता यह थी कि यदि पार्टी सपा की दी हुई कम प्रभाव वाली सीटों पर लड़ेगी, तो इससे न केवल उसका इस चुनाव में नुकसान होगा, बल्कि पार्टी हमेशा के लिए यूपी में कमजोर हो जाएगी। सपा ने कांग्रेस को वे सीटें भी दी थीं, जहां पर उसके परंपरागत मतदाताओं का ज्यादा प्रभाव नहीं था, यही कारण है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन अंततः टूटने की कगार पर पहुंच गया था।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, लेकिन अंतिम समय में प्रियंका ने बात संभाली। उन्होंने अखिलेश यादव को बताया कि यदि वे साथ नहीं लड़ते हैं, तो इससे केवल इस चुनाव में ही हार नहीं होगी, बल्कि विपक्ष की आगे की चुनावी राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि अंततः दोनों दलों के बीच समझौता हो गया।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने अमर उजाला को बताया कि जब दिल्ली में यूपी के नेताओं से राहुल गांधी की बातचीत हुई थी, उसी समय राहुल गांधी ने यह बात कह दी थी कि यदि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता है और गठबंधन में रहकर 15-20 सीटों पर लड़कर कांग्रेस चार-पांच सीटें जीत भी लेती है, तो इससे पार्टी का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। राहुल के अनुसार, भविष्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए उसे रणनीति बनाकर लंबे समय तक उस पर काम करना होगा। राहुल गांधी पार्टी का आधार मजबूत करने की बात करते रहे हैं, लेकिन सपा जिस तरह से सीटों का बंटवारा कर रही थी, उससे कांग्रेस का कोई उद्देश्य हल नहीं हो रहा था। न तो पार्टी को ज्यादा सीटें ही मिल रही थीं, न ही उसका आधार मजबूत हो रहा था। यही कारण है कि गठबंधन के टूटने का खतरा पैदा हो गया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव ने उनके सामने दो विकल्प छोड़े थे। एक- वे उनकी दी हुई कमजोर सीटों पर लड़ें और हार जाएं। इससे पार्टी की रही सही ताकत भी समाप्त हो जाएगी। इससे पार्टी के सामने यूपी में हमेशा के लिए समाप्त हो जाने का खतरा पैदा हो सकता था। पिछली बार सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट जीत ली थी। लेकिन इस बार वे भी मैदान में नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने शून्य पर सिमट जाने का खतरा पैदा हो सकता था।

दूसरा विकल्प यह था कि सीटों पर बात न बनने के आधार पर कांग्रेस स्वयं गठबंधन से बाहर होने की घोषणा कर दे, जिससे गठबंधन से बाहर जाने का दाग अखिलेश यादव पर न लगे। इस स्थिति में नुकसान यह हो सकता था कि पार्टी को ज्यादा सीटों पर सफलता न मिलती। हालांकि, इसका एक लाभ यह हो सकता है कि कांग्रेस बाकी सीटों पर चुनाव लड़ती और हर सीट पर उसका प्रचार होता। कांग्रेस इस चुनाव का लाभ उस दलित-पिछड़े-मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने में करने का प्लान बना रही है, जिसके सहारे वह अपनी दूसरी पाली में खड़ी होने का सपना देख सकती है। लेकिन अखिलेश के फॉर्मूले से पार्टी के यह उद्देश्य पूरा न होता। नेता के अनुसार, पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कानपुर के बाद झांसी के रास्ते मध्यप्रदेश ले जाने की तैयारी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इस रूट से इसलिए अलग रखा गया था, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 1.0 में ही इसे कवर कर लिया गया था। लेकिन बाद में यात्रा का रूट बदलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसका दो बड़ा कारण था- पहला तो कांग्रेस अखिलेश यादव को यह संदेश देना चाहती थी कि वह उनके दबाव में एक सीमा से आगे नहीं जाएगी। वह अपने उस कोर वोट बैंक और कोर एरिया से समझौता नहीं करेगी, जहां उसके मजबूत होने की संभावनाएं हैं। दूसरा- पूरे देश में इस समय मुसलमान मतदाता कांग्रेस के पक्ष में एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में ऐन चुनावों के मौसम में पार्टी के लिए यह ज्यादा सही होगा कि वह मुसलमान मतदाताओं के बीच पहुंचे और उन्हें अपने से एकजुट होने का संदेश दे। राहुल गांधी की यात्रा बिहार से पश्चिम बंगाल तक हर उस एरिया से गुजरी है, जहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी की यात्रा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ा गया।

सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। पिछले कुछ घंटों से दोनों ओर से फायरिंग जारी है। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने नक्सल मुठभेड़ की पुष्टि की है।

जानकारी के अनुसार, बस्तर फाइटर्स, डीआरजी, सीआरपीएफ, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के जवानों की संयुक्त टीम बुधवार को सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान गंगालूर क्षेत्र के पीडिया के जंगलों में घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले के बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल, नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है।

इससे पहले 17 फरवरी को भी दंतेवाड़ा में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुआ था। जिसमें नक्सल विरोधी अभियान पर निकली सुरक्षाबलों की टीम पर नक्सलियों ने जिले के रामपुर गांव के समीप हमला किया था। सुरक्षाबलों की ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई करने पर नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया था। जवानों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मौके लसे बरामद किए थे।

नक्सलियों ने कहा एसपी-थानेदार का था मुखबिर, हमने मार डाला

दंतेवाड़ा। जिले में दो दिन पहले बारसूर थाना क्षेत्र अंर्तगत घोटिया चौक के पास एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त चैनु कश्यप के रूप में हुई थी, इस युवक की हत्या पर संशय बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद में आपसी रंजिश में हत्या की आशंका है, जबकि नक्सलियों की तरफ से जारी किए गए एक और पर्चे में कहा गया है कि यह एसपी और थानेदार का मुखबिर था, इसलिए हमने मार डाला। नक्सलियों जारी पर्चे में कहा है कि युवक गोपनीय सैनिक बनकर काम कर रहा था।

बारसूर थाना क्षेत्र के घोटिया चौक के पास मिले युवक चैनु कश्यप की हत्या के मामले में अब नक्सलियों की पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने एक और पर्चा जारी किया है। नीली स्याही से लिखे पर्चे में नक्सलियों ने युवक को पुलिस का मुखबिर बताया है। नक्सलियों ने कहा है कि चैनु कश्यप दंतेवाड़ा के एसपी और बारसूर के थानेदार के कहने पर गोपनीय सैनिक बन गया था। यह उनके लिए काम करता था। जिसके बाद पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी ने इसे मौत की सजा दे दी।

विदित हो कि युवक चैनु कश्यप का शव मिलने के बाद पुलिस की तरफ से भी एक बयान आया था जिसमें कहा गया कि इसका इसके परिवार के साथ विवाद चल रहा था। इसी वजह से आपसी रंजिश में हत्या की आशंका है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। युवक की हत्या कैसे हुई, इस पर अब भी संशय बना हुआ है।

1 नक्सली मिलिशिया सदस्य ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान पूना नर्कोम अभियान-नई सुबह-नई शुरुआत के तहत नक्सली संगठन में सक्रिय 1 नक्सली कवासी हांदा पिता जोगा (बेड़मा आरपीसी अन्तर्गत मिलिशिया सदस्य) के द्वारा बुधवार को नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में उत्तम प्रताप सिंह, उप पुलिस अधीक्षक बस्तर फाईटर्स सुकमा एवं निरीक्षक रमेश सिंह 223 वाहिनी सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसर्मर्पित नक्सली को समर्पण कराने में 223 वाहिनी के आसूचना शाखा का विशेष योगदान रहा। आत्मसमर्पित नक्सली को शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत सहायता राशि व अन्य सुविधाए प्रदाय किये जायेंगे।

बलरामपुर नगरीय क्षेत्र में पहुच रहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा

बलरामपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने एवं शासन की लोक हितैषी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है यह यात्रा 20 से 24 फरवरी तक जारी रहेगा। जिसमें जिले के नगरीय क्षेत्रों में निर्धारित स्थानों में कार्ययोजना अनुसार सतत रूप से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प शिविर नगर पंचायत कुसमी, राजपुर में शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविर स्थलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोबाइल वैन भी पहुंच रही है। जिसका स्वागत नगरवासियों द्वारा पारंपरिक तरीके से किया गया। मोबाइल वैन के एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संदेश का वाचन करने के साथ ही लघु चलचित्रों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य की जानकारी आमजनों को दी गई।

शिविर में शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने एवं योजनाओं का लाभ लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शिविर में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत हितग्राहियों द्वारा विभिन्न योजनाओं से मिले लाभ के संबंध में अपने अनुभव साझा करते हुए आमजनों को योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित किया एवं बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। शिविरों में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आधार अपडेशन, सस्ती व अच्छी जेनेरिक दवाई आदि की जानकारी देने के साथ योजनाओं से वंचित हितग्राहियों से आवेदन लेने के साथ-साथ उनकी समस्याओं का भी समाधान किया गया। शिविर स्थल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में बीपी, शुगर की जांच तथा दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा अन्तर्गत कैलेण्डर का भी वितरण किया गया।

वन विभाग ने कटीले तारों से तांदुला जलाशय को घेरा

रेंजर बोले- वन्य प्राणी कूदकर पी सकते हैं पानी

बालोद। जीवन दायिनी तांदुला जलाशय जो कि मानव जीवन के साथ-साथ वन्य प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, परंतु हाल ही में वन विभाग द्वारा इस जलाशय को चारों ओर से कटीले तार फेंसिंग से घर दिया गया है। लगभग 6 से 8 फीट की इस घेराई के बाद सवाल यह उठता है कि आखिर वन्य प्राणी अब जलाशय से पानी कैसे पी पाएंगे। वहीं, जंगल में खोदे गए तालाब भी ज्यादातर सूखे ही हैं, ऐसे में वन विभाग के रेंजर का बयान आता है कि वन्य प्राणी तार से कूदकर जलाशय तक पहुंच सकते हैं।

दरअसल, तांदुला जलाशय वन्य क्षेत्र का एक हिस्सा है। यहां पर वन्य प्राणियों का जमावड़ा रहता है। तेंदुए से लेकर हिरण नील गाय अक्सर देखे जाते हैं। ऐसे में इस जगह को चारों ओर से घेर दिया गया है। इससे जलाशय की जो खूबसूरती है वो तो घटी ही है। साथ ही भीषण गर्मी में वन्य प्राणियों को भी तकलीफ होने वाली है। रेंजर हेमलता उइके ने पूरे मामले पर कहा कि वन्य प्राणी नील गाय ऊपर से कूदकर जलाशय तक जा सकता है और एक जगह रास्ता छोड़ा गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मूकबधिर जानवर प्यास में पानी के पास जाने के लिए तार घेरे के खत्म होने का इंतजार करेंगे।

यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष साजन पटेल ने पूरे मामले पर वन विभाग को घेरा और कहा कि समझ नहीं आता कि आखिर इसे क्यों घेरा गया है। वन्य प्राणी जलाशय तक अपनी प्यास बुझाने आखिर पहुंचेंगे कैसे और वन विभाग का यह भी कहना है कि जंगल में तालाब खोदे गए हैं। लेकिन जो तालाब खोदे गए हैं, वे सूखे पड़े हैं। उसमें पानी भरने का कोई साधन ही नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले को सीधे-सीधे जेब भरने का साजिश करार दिया है। वहीं, बालोद निवासी तरुण नाथ योगी ने कहा कि इस जगह को हम बचपन से देख रहे हैं। पहली बार इसे घेर दिया गया है। हम सुबह वॉक करने आते हैं तो देखते हैं जानवर प्यासे बेबस कटीली तार के बाहर खड़े रहते हैं। आखिर इसमें वन्य प्राणियों का भला कैसे होगा।

जंगल के बीच में खोदे गए ज्यादातर तालाब सूखे हैं, जिसके कारण वन्य प्राणियों को जलाशय तक जाना अनिवार्य है, लेकिन तालाब को भरने के लिए मानसून का इंतजार करना पड़ेगा और यह तीन महीने का समय वन्य प्राणियों के लिए कहीं घातक सिद्ध न हो जाए और कुछ तो नए तालाब बनाए गए हैं, वहां पानी का एक बूंद नहीं है। वहीं, जलाशय प्रकृति का इतना बड़ा स्रोत है उसे घेर दिया गया है।

जिस जगह को तार से घेरा गया है, वह वन्य प्राणियों का विचारण क्षेत्र है। यहां पर नील गाय की बहुलता है और अक्सर हम देखते हैं की डिहाइड्रेशन दुर्घटना तार फेंसिंग में फंसने के कारण घायल होने की सूचना मिलते ही रहती है। अब देखना यह होगा कि पूरे मामले पर वन विभाग का स्टैंड क्या रहता है, क्योंकि तार घेरे करते समय कुछ नियमों को भी दरकिनार किया गया है।

बस्तर में नियद नेल्ला नार योजना की शुरुआत

■ बस्तर कमिश्नर ने दिया दिशा निर्देश विकास को मिलेगी रफ्तार

बस्तर। बस्तर के नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में समग्र विकास को लेकर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार नई योजना लेकर आई है। साय शासन ने नियद नेल्ला नार नाम से नई योजना शुरु की है। नियद नेल्ला नार का अर्थ है- आपका अच्छा गांव। बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के संभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की और जरूरी दिशानिर्देश दिए है।

संभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक संभागायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित गांवों में अधोसंरचना विकास सहित मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने मिशन मोड पर काम करने कहा है। बैठक में बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने कहा है, इन इलाकों के स्थानीय ग्रामीणों के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देकर विकास का उजियारा चारों ओर पहुंचायेंगे।

बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने योजना के तहत बस्तर अंचल के 58 गांवों में विकास कार्यों को पहुंचाने और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। ये 58 गांव बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिलों में 16 नवीन कैम्पों के समीप स्थित हैं। उन्होंने इस दिशा में चिन्हित 32 योजनाओं और सेवाओं के कारगर क्रियान्वयन पर फोकस करने की जरूरत बताई है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, मोबाइल टॉवर इत्यादि बुनियादी विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। ताकि बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बनाए गए नए कैम्प सुरक्षा के साथ विश्वास और विकास के कैंप साबित हो सकें।

बस्तर कमिश्नर ने स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने इन नवीन कैम्पों के समीपवर्ती गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर फोकस करने पर जोर दिया है। साथ ही शासन की आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड प्रदाय सुनिश्चित करने कहा है। ताकि जरूरतमन्द लोगों को उपचार संबंधी समुचित सहायता मिल सके। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और उनकी संस्थागत प्रसव सुविधा जौसी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कहा है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित 16 नए सुरक्षा कैंपों में नवाचार के रूप में विकास कार्य किए जा रहे हैं। कैम्पों के आसपास स्थित करीब 5 गांवों की मूलभूत आवश्यकता के नजरिये से अधोसंरचना विकास और परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। संवेदनशील क्षेत्रों के सम्बंधित ग्रामों में शासन की 32 व्यक्ति मूलक योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर फोकस किया जा रहा है।

बस्तर कमिश्नर ने नवीन कैम्पों से सम्बंधित ग्रामों के चिन्हित जरूरतमंद परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने कहा है। साथ ही नि:शुल्क बिजली की सुलभता, राशनकार्ड, मुफ्त खाद्यान्न, जरूरी सामग्रियों की उपलब्धता और उज्जवला योजना से लाभान्वित किये जाने कहा है। इन गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल, उप स्वास्थ्य केन्द्र के बेहतर संचालन के लिए सर्वेक्षण कर क्रियान्वयन पर जोर देने निर्देश दिया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

स्कूल जा रही छात्रा को चलती गाड़ी से कुत्ते ने खींचा

कोरबा। स्टेटस सिंबल के साथ-साथ आजकल सुरक्षा की दृष्टिकोण से आर्थिक रूप से सक्षम लोगों में कुत्ता पालने का शौक कुछ ज्यादा ही बना हुआ है। समस्या तब होती है जब शौकीन लोग कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं। खरमोर क्षेत्र में इसी चक्कर में एक स्कूली छात्र कुत्ते के हमले का शिकार हो गई। यह मामला सिविल लाइन थाना पहुंच गया। पीड़ित पक्ष ने कुत्ते के मालिक पर कार्रवाई करने की मांग की है। वफादारी के किस्सों की जब बात होती है तो उसमें कई चीजे शामिल की जाती हैं और इस दौरान कुत्तों का जिक्र भी होता है। कई मामलों में देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर जरूर है। लेकिन कुत्तों से दूसरे लोगों की सुरक्षा को लेकर उदासीन बने हुए हैं। खरमोरा में हुई एक ऐसी घटना में विश्राम सिंह पटेल की सुपुत्री को स्कूल जाने के दौरान कुत्ते ने जख्मी कर दिया। बालिका के चिल्लाने पर उसके पिता हरकत में आए और उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया। विश्राम पटेल ने बताया कि उसकी बेटी क्लास तीन की छात्रा है और निर्मला स्कूल में पढ़ती है।

शिक्षक बना पापी, भगवान की पूजा के पैसे शराब में उड़ाए

कांकेर। जिले के पखांजुर क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक शाला पीवी 20 में पदस्थ प्रधानपाठक रोजाना शराब के नशे में धुत्त होकर स्कूल आता है। शिक्षक 13 साल से यहां पदस्थ है। आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब वह बिना शराब पीए स्कूल आया हो। शराब के नशे में साथी शिक्षकों, रसोइया को परेशान करता है। छात्रों की पिटाई भी करता है। इस बार तो शिक्षक ने स्कूल में बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा मनाने छात्रों द्वारा किए चंदे के पैसे शराब में उड़ा दिए। इस मुद्दे को लेकर आयोजित बैठक में भी प्रधानपाठक शराब पीकर पहुंचा तो ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। शराबी प्रधानपाठक का वीडियो बना वायरल कर दिया गया। इसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया तथा मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय दल को स्कूल भेजा। प्राथमिक शाला पीवी 20 में प्रधानपाठक सुनील करभाल 13 सालों से पदस्थ है। रोज शराब पीकर आने की शिकायत ग्रामीण तथा छात्र करते रहे, लेकिन शिक्षा विभाग ने शराबी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर उल्टे उसका प्रमोशन करते प्रधान पाठक बना दिया।

कृमिपालन और कोसा उत्पादन से महिलाएं बनी स्वावलंबी

जांजगीर चांपा। स्व सहायता समूह की महिलाएं स्वावलंबन की डगर पर आगे बढ़ रही है। रेशम विभाग के कोसा कृमिपालन से जुड़कर आत्मनिर्भर भी बन गई है। जांजगीर चांपा जिले के विकास खंड पामगढ़ के ग्राम खोरसी की महिलाएं अमरीका साहू, संतोषी साहू, निशा साहू, छटबाई साहू, दुलेशवरी साहू, चंद्रीका साहू ने अर्जुन के पेड़ों पर रेशम से कृमिपालन से कोसाफल उत्पादन का काम शुरू किया है। महिलाओं ने बताया कि पहले अपने खेतों में खरीफ की फसल लेने के बाद सालभर मजदूरी की तलाश में रहते थे। आज महिलाओं की आंखों में सफलता की खुशी साफ नजर आ रही है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। समूह की महिलाओं ने बताया कि रेशम विभाग के मार्गदर्शन में कोसा कृमिपालन स्वावलंबन समूह खोरसी से सभी महिलाओं ने जुड़कर कृमिपालन और कोसाफल का उत्पादन, संग्रहण का कार्य शुरू किया। महिलाओं ने 3 सालों में लगभग 3 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर ली है।

पुलिस का खौफ खत्म! पैदल जा रही युवती से दिनदहाड़े लूट

अभनपुर। रायपुर के अभनपुर में दिनदहाड़े लूट का मामला सामने आया है। राह चलती युवती के हाथ से बैग छीनकर एक्टिवा सवार 2 लुटेरे फरार हो गए। वहीं लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर अभनपुर पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना से सवाल उठने लगे हैं कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार, 17 फरवरी की दोपहर 3 युवतियां बड़े उरला की ओर जा रही थी। इसी बीच मिनीमाता चौक पर एक एक्टिवा में सवार 2 अज्ञात युवक आए और तीनों युवतियों में से एक युवती के हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है बैग में मोबाइल, आधार कार्ड, एटीएम सहित अन्य सामान थे। पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित युवती ने घटना की शिकायत 19 फरवरी को अभनपुर थाने में दर्ज करवाई है। जिसपर अभनपुर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

बेमेतरा में 230215 राशनकार्ड नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त

बेमेतरा। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक राशनकार्डों के समयबद्ध नवीनीकरण के संबंध में शासन निर्देशानुसार प्रचलित समस्त अंत्योदय राशनकार्ड, प्राथमिकता राशनकार्ड, निराश्रित राशनकार्ड, नि:शक्तजन राशनकार्ड तथा सामान्य राशनकार्ड के नवीनीकरण का कार्य प्रचलित है। जो कि 29 फरवरी 2024 तक पूर्ण किया जाना है। ज़िला खाद्य अधिकारी श्री नीतीश त्रिवेदी ने बताया कि आवेदन की प्राप्ति तथा नवीनीकृत राशनकार्ड प्रदाय हेतु निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की गई है-हितग्राही द्वारा आवेदन की समय-सीमा 25 फ़रवरी 2024 तक है। हितग्राही को राशनकार्ड का प्रदाय 01. फ़रवरी 2024 से 29 फ़रवरी 2024 तक किया जाएगा। अधिकारी श्री त्रिवेदी ने बताया कि जिला अंतर्गत राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में प्रचलित कुल 268134 राशनकार्डो के विरुद्ध 230215 (85.86ब) आवेदन नवीनीकरण हेतु प्राप्त हुए है, 37904 राशनकार्ड के नवीनीकरण आवेदन अब तक प्राप्त नही हुए।

सरगंवा पंचायत की हर दूसरी महिला किसान है लखपति

सरगुजा। गांव गांव में महिलाओं को सशक्त बनाने सरकार कई योजनाएं चल रही हैं। लेकिन कुछ योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सरगंवा पंचायत की महिलाएं इन्हीं योजनाओं का फायदा उठाकर महीने भर में ही करीब 1 लाख रुपये की कमाई कर रही है।

सरगंवा पंचायत में 52 समूह है। क्षेत्र की 520 महिलाएं इन समूहों से जुड़ी है। इन महिलाओं में से 406 ऐसी महिलाएं हैं जो समूह के जरिए लोन लेकर खेती, मुर्गी, मछ्ली, बतख पालन, कड़कनाथ पालन कर अच्छी कमाई कर रही है। इन समूहों का लगभग 5 करोड़ 10 लाख का लोन स्वीकृत हुआ है। ऐसी ही कुछ महिलाओं को बारे में आपको बता रहे हैं जो खेती कर लखपति महिला किसान बन गई हैं।

सरगंवा की 32 वर्षीय महिला सीमा विश्वास जिनके पास खुद की महज 2 एकड़ जमीन है, लेकिन वो 4 से 5 एकड़ जमीन लीज पर लेती हैं और अलग अलग तरह की खेती कर लाभ कमा रही हैं। सीमा ने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से ट्रेनिंग ली और 4 लाख का लोन

लेकर खेती शुरू की। मक्के की खेती में ढाई लाख का मुनाफा हुआ। ये मुनाफा सिर्फ 5 महीने की मक्के की फसल से मिला। इसके अलावा खीरा की 1 एकड़ की फसल में सिर्फ 30 से 35 हजार की लागत में डेढ़ लाख का फायदा हुआ। गोभी की फसल से भी लगभग डेढ़ लाख की कमाई हुई। समूह से साढ़े 4 लाख का लोन लेकर खेती कर रही है। हर महीने 75 हजार रुपये की कमाई कर रही है। खेती के अलावा सीमा गाय पालन भी करती हैं और दूध बेचकर पैसे कमाती हैं। सीमा से प्रेरित होकर क्षेत्र की कई महिलाओं ने खेती किसानी शुरू कर दी और लाभ कमा रही है।

महिला किसान सीमा विश्वास ने कहा शादी होकर जब सरगंवा आई थी। हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं थी। घर की हालत भी काफी खराब थी। जो जमीन थी उस पर भी खेती नहीं होती थी। साल 2014 से खेती शुरू की। जो जमीन थी उस पर पहली बार 50 किलो आलू लगाए जिस पर पहली बार 20 हजार रुपये का फायदा हुआ। तब से हमने किराए पर जमीन लेकर खेती करना शुरू कर दिया। काफी फायदा हो रहा है। पहले मिट्टी का घर था अब अच्छा घर बना लिए हैं। बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं।

पति की मौत के बाद भी नहीं छोड़ी खेती- ऐसी ही एक और महिला किसान है नमिता राय। नमिता के पति का निधन साल 2017 में हो गया। दो बच्चे हैं। एक बूढ़ी सास है। पति की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी नमिता पर आ गई। पति पत्नी मिलकर पहले से ही खेती करते थे। पति की मौत के बाद नमिता ने खेती के काम को आगे बढ़ाया। समूह से लोन लेकर अलग अलग खेती करने लगी।

महिला किसान नमिता राय ने कहा साग सब्जी, मटर, केला, गांठगोभी की खेती करती हूं। फसल को साप्ताहिक बाजार में बेचती हूं। इसके अलावा गाय, बतख और कड़कनाथ मुर्गी भी पालती हूं। दूध, अंडे, बतख और मुर्गियां भी बेचती हूं। खेती से ही घर चल रहा है। समहू से लोन लेकर काम को आगे बढ़ाती हूं। जागृति समूह से जुड़कर सरगंवा की महिलाएं लोन ले रही है और अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रही हैं। छोटी सी ही जगह पर कई अलग अलग खेती कर रही है।

जगतरा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं, कराई जाती है मजदूरी!

बालोद। जिले के नेशनल हाइवे-30 में स्थित जगतरा गांव के हाईस्कूल में पढ़ाई नहीं बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। हाईस्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल बच्चों को रापा और धमेला पकड़ाकर मजदूरों की तरह काम कराते पाए गए हैं। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं या मजदूरी करने।

बता दें कि जगतरा गांव के हाईस्कूल स्कूल में क्यारी और मंदिर का निर्माण शाला के आकस्मिक निधि से कराया जा रहा है। जहां पैसे बचाने के लिए मजदूरों के बजाया बच्चों से काम लिया जा रहा है। बच्चों ने नाम नहीं बताने की शर्त में बताया कि आज काम करने के लिए मिस्त्री नहीं आए हैं और हमे हमारे प्रभारी प्रिंसिपल ने कड़कती धूप में काम करने कहा है, इसलिए काम कर हैं। अब जैसा सर कहेंगे वही तो हम करेंगे। पूरे मामले को मीडिया के कैमरे में कैद होते देख प्रभारी प्रिंसिपल ने अपना नाम तक बताना मुनासिफ नहीं समझा और गैरजिम्मेदाराना बयान देते हुए यह कह दिया कि अब आपको जो करना है करो। वहीं पूरे मामले में संवेदनशील कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल को लल्लूराम डॉट काम के रिपोर्टर के माध्यम से जानकारी दी गई तो उन्होंने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है।

बिरनपुर हिंसा की होगी सीबीआई जांच, उप मुख्यमंत्री शर्मा की विधानसभा में घोषणा

रायपुर। विधानसभा में बुधवार को बिरनपुर में हुई हत्या का मामला उठा। ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने मामला उठाते हुए कहा कि घटना के वक्त सीबीआई जांच की बात कही गई थी। क्या सीबीआई जांच कराई जाएगी? इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में घोषणा की कि बिरनपुर मामले की सीबीआई से जांच कराई जाएगी।

ईश्वर साहू ने सदन में कहा कि 8 अप्रैल को हुई घटना में भुवनेश्वर साहू की हत्या में 34 आरोपी के नाम सामने आये थे, इनमें 12 आरोपियों की गिरफ़्तारी हुई, बाकी आरोपी गिरफ़्तार क्यों नहीं हुए? इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक समाज के चार स्कूली बच्चों के बीच विवाद की स्थिति के बाद समाज ने सुलह के लिए बैठक रखी थी। इस बैठक के बाद भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भागीरथी साहू की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था। 8 अप्रैल को 11 आरोपियों की गिरफ़्तारी की गई। एक अन्य की गिरफ़्तारी बाद में की गई। अभियोग पत्र 5 जुलाई को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। मामले की विवेचना जारी है। इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि अंजोर यदु ने घटना की शुरुआत की थी, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई।

विजय शर्मा ने कहा कि मैने स्पष्ट किया है गांव में जो घटना हुई भुनेश्वर साहू की हत्या हुई। न्याय की लड़ाई लड़ते-लड़ते उनके पिता आज सदन में अपनी बात कह रहे हैं, यह अद्भुत संयोग है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कि इस प्रकरण में सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत विवेचना जारी। जिस संदर्भ में बातचीत हुई उचित प्रमाण मिले वह जेल में है, परंतु जिनके संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ, उनकी विवेचना जारी है। 40 लोगों के नाम दिए गए थे, उसमें 12 लोग के नाम एफआईआर थे उन सभी के संबंध में विवेचना जारी है आगे भी करवाई जारी रहेगी।

ईश्वर साहू ने कहा कि विशेष समुदाय के लोगों के पास सैकड़ो हथियार हथियार थे उसे समय अधिकारियों ने कहा था कि उसे जप्त करेंगे लेकिन अभी तक जब तक क्यों नहीं हुए? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि इसमें संबंध में जो भी हथियार उपयोग किया गया था, उन सब को जमा किया गया है कुछ हथियारों को एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। गांव में पुलिस चौकी है, और यह निर्धारित किया जा रहा है कि गांव में कोई बड़ा हथियार नहीं है।

ईश्वर साहू ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि अवैध हथियार कब तक जप्त किया जाएगा? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि एक बार गांव में सभी घरों में बातचीत चर्चा गांव के माध्यम से करके और जहां आवश्यकता हुई वहां तलाशी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि

कोई बड़ा हथियार किसी की घर में ना, हो या सुनिश्चित करेंगे।

ईश्वर साहू ने इस पर कहा कि मैं स्वयं मृतक का पिता हूं मैं सदन से जानना चाहता हूं मुझे न्याय मिल पाएगा या नहीं? और मिलेगा तो कब तक मिलेगा? विजय शर्मा ने जवाब में कहा कि उनके प्रश्न और विषयों को लेकर के मैं अभिभूत हूं। हर हाल में हम सब मिलकर उनको न्याय मिले, उनको और उनके मन में जो बातें हैं, वह सारी बातें ठीक हो। उन सारे विषय को ठीक हो वह सारी जानकारी हो जाए। मैं भी चाहता हूं, इसके लिए जैसी आवश्यकता होगी वह पूरा करेंगे।

ईश्वर साहू ने इस पर कहा कि घटना के समय अधिकारियों द्वारा सीबीआई जांच करवाने का आश्वासन मिला था करवाएंगे कि नहीं? विजय शर्मा ने कहा कि जांच जारी है एसआईटी बनाकर जांच की जा रही है, फिर भी एक पराक्रमी पिता के हृदय का दर्द है, इसलिए मैं आज सदन में घोषणा करता हूं कि इस विषय में सीबीआई जांच करवाई जाएगी। ईश्वर साहू ने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, तो मैं क्या अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या न्याय दिला पाऊंगा।

अजय चंद्राकर ने इस पर सवाल किया कि सीबीआई जांच करेंगे, क्या उसमें एक एंगल और है। इस घटना के बाद एक समुदाय विशेष के दो लोगों की भी हत्या हो गई। हत्या किन परिस्थितियों में हुई, वह हत्या प्रतिक्रिया के स्वरूप है, या किसी दल विशेष में चुनाव सामने था, इसलिए षडयंत्रपूर्वक उन दोनों की हत्या करवाई गई। क्या इस विषय को भी इस एंगल से भी क्या इस विषय को भी सीबीआई जांच में शामिल करेंगे। हत्या प्रतिज्ञा शुरू हुई, किसने की, क्या यह विषय भी आप सीबीआई जांच में शामिल करेंगे।

इस पर विजय शर्मा ने कहा कि 11 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई मामला न्यायालय में है। चालन प्रस्तुत हो चुका है। 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, इसलिए न्यायालय के निर्णायक प्रतीक्षा करें। ईश्वर साहू ने जो बात रखी, उसे विषय में सीबीआई जांच कराई जाएगी। इसमें हर विषय का सीबीआई जांच नहीं कराई जा सकती, अब सदन का निर्णय है।

अजय चंद्राकर ने इस पर कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं बहुत रेयर है। मैं इस एंगल से बात नहीं कर रहा हूं कि मर्डर है। 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मतलब है कि दो लोगों की हत्या हुई वह साजिश थी कि हत्या की घटना है, सिर्फ इसी मुद्दे को सीबीआई में शामिल करेंगे क्या। इसके साथ विधायक गजेंद्र यादव ने सवाल किया कि कवर्धा के लालपुर में सदाराम की भी हत्या की गई है। उस पर भी कुछ होगा क्या?

इस पर विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा में को घटना हुई। साधराम गौशाला में काम करते थे। उनकों चार लोगों ने पीछे से पकड़ा और किसी ने बाल पकड़ के धीरे-धीरे गला काटा है। यह हत्या हथियार से नहीं, विचार से है। इसमें यूएपीए का एक्ट लगा है। मैं खुद गया था, और 5 लाख रुपए की राशि मैंने दी है, जो मेरे से हो सकता था। मैंने मुख्यमंत्री से बात की है और जो आर्थिक सहायता है वो परिवार को मिलेगी।

बिरनपुर हत्याकांड की सीबीआई जांच पर भूपेश बघेल ने कसा तंज

रायपुर। बिरनपुर हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं है। यह सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा बिरनपुर हत्याकांड की जांच कराए जाने की घोषणा पर सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा और वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को जोर-जोर से उठाया था। यह निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में ही ले लिया जाना था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं है, यह सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है। पीड़ित व्यक्ति ने ध्यानाकर्षण लगाया तब इसकी घोषणा हुई। सीबीआई जांच का हश्र हमने देखा है, यह एक घोषणा भर रहेगी। यह सरकार की नाकामी प्रदर्शित करता है।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री को महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने दिया जन्मदिन पर तोहफा

रायपुर। बुधवार को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जन्मदिन था। इस मौके पर हर कोई अपने लाडले मुख्यमंत्री को बधाई दिया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने भी अपने अंदाज में मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सरस मेला में शामिल होने आए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को स्व सहायता समूह की महिलाओं ने उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने मिलेट्स के बने लड्डुओं को 60 के आकार में थाल में सजाकर मुख्यमंत्री को उपहार स्वरूप भेंट किया। दरअसल ये मुख्यमंत्री का साठवां जन्मदिन है इसलिए खास तौर पर 60 के आकार में लड्डुओं को सजाकर महिलाओं ने इसे तैयार किया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा की छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूह की बहने आर्थिक स्वावलंबन की नई कहानी लिख रही हैं और आने वाले समय में वो विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को पूरा करने में अपना अहम योगदान देने वाली हैं।

राजधानी के मोबाइल और मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग

रायपुर। राजधानी रायपुर के भांटागांव स्थित एक मोबाइल और मेडिकल स्टोर में आज भीषण आग लग गई। इससे दोनों शॉप से लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आकाश मोबाइल और हरिओम मेडिकल दुकान में आग लगी थी। फिलहाल आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रायपुर संभाग में 169 नोटरी हैं कार्यरत

रायपुर। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में बुधवार को विधायक संपत अग्रवाल ने रायपुर संभाग के नोटरियों के संबंध में प्रश्न किया। विभागीय मंत्री अरुण साव ने सदन में बताया कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में रायपुर संभाग में कुल 169 नोटरी कार्यरत थे। दिसंबर 2023 की स्थिति में 47 ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। इसमें से 36 का नवीनीकरण हो गया है। 11 मामले लंबित हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विभागीय मंत्री से कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में बड़ी संख्या में नए जिले और तहसील आदि का गठन किया गया है। ऐसे में नोटरी के पद भी रिक्त हैं, उन्हें कब तक भरा जाएगा। इस पर मंत्री साव ने बताया कि उन्होंने विभाग से पूरी जानकारी मांगी गई है। जैसे ही जानकारी उपलब्ध हो जाएगी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

राज्यपाल ने 'द बर्डस् इन द स्टार्म' पुस्तक का किया विमोचन

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने गत दिवस राजभवन में डॉ. भगवान जयसिंह द्वारा संपादित पुस्तक ''द बर्डस् इन द स्टार्म'' का विमोचन किया। डॉ जयसिंह ओड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं अनुवादक हैं। इस पुस्तक में अनेक विख्यात ओड़िया कवियों की लगभग 80 कविताओं का संकलन किया गया है। कार्यक्रम में श्री माधव कौशिक, अध्यक्ष केन्द्रीय साहित्य अकादमी सहित छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के अनेक साहित्यकार एवं लेखक उपस्थित थे। राज्यपाल श्री हरिचंदन ने डॉ. जयसिंह को उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डॉ. जयसिंह एक बहुत अच्छे अनुवादक हैं। डॉ. जयसिंह ने राज्यपाल की आत्मकथा ''बैटल नॉट यट ओवर'' का ओड़िया से अंग्रेजी में उत्कृष्ट श्रेणी का अनुवाद किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के साहित्यकारों का अभिवादन किया और कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति पर खुशी व्यक्त की।

विद्यार्थी जीवन में अनुशासन जरूरी : बृजमोहन

■ विज्ञान महाविद्यालय के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में हुए शामिल

रायपुर। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन जरूरी है। अनुशासन से ही हमें ज़िंदगी में सफलता की राह मिलती है। जब हम लक्ष्य तय करते हैं, तो अनुशासन ही हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन ने शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में कहीं । कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अनुशासन हमें अपने समय का सदुपयोग करने में मदद करता है। जब हम अनुशासित होते हैं, तो हम अपना समय ज़रूरी कामों में लगाते हैं और व्यर्थ की गतिविधियों में समय बर्बाद नहीं करते हैं।

अनुशासन हमारी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम अनुशासित होते हैं, तो हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और आसानी से विचलित नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि अनुशासन से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम अनुशासित होते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अनुशासन हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। जब हम अनुशासित होते हैं, तो हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, स्वस्थ भोजन करते हैं और पर्याप्त नींद लेते हैं।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि याद रखें, अनुशासन एक आदत है, इसे बनाने में समय लगता है। यह एक ऐसी आदत है जो आपको ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। कॉलेज के दिन

आपके जीवन के सबसे यादगार दिनों में होंगे। अनुशासन के साथ, आप इन दिनों का भरपूर आनंद ले सकते हैं और ज़िंदगी में सफलता भी प्राप्त कर सकते है।

उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ एथिक्स, संस्कार, संस्कृति, अध्यात्म योग प्राणायाम के साथ ही गीत संगीत और खेल कूद भी शामिल करना चाहिए, यह विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने रुचि के अनुसार कैरियर का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना देखा है, जिसको पूरा करने के लिए हमको पढ़ाई के साथ-साथ दूसरे क्षेत्रों में भी आगे आना होगा। उच्च शिक्षा शोध और नवाचार आदि से जुड़ी होनी चाहिए। सभी क्षेत्रों में हमको नंबर वन बनना होगा।

इस अवसर पर श्री ज्ञानेश शर्मा, अलुमनई एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अंजय शुक्ला, प्राचार्य डॉ पीसी चौबे, श्री एनबी सिंह, श्रीमती रेणु माहेश्वरी समेत कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण उपस्थित थे।

फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र से तैयार हुआ उसना राइस मिल, सदन में विधायक ने उठाया मुद्दा

बालोद। बालोद जिले के गुरुर ब्लॉक के ग्राम पलारी में अवैध रूप से उसना राइस मिल बनकर तैयार हो चुका है। स्थानीय आरआई और पटवारी द्वारा फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है। विधानसभा में विधायक संगीता सिन्हा ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। विधायक संगीता सिन्हा ने पूरे मामले में ध्यानाकर्षण लाया है।

विधायक ने बताया कि यह उसना राइस मिल में बसाहट से मात्र 19 मीटर की दूसरी पर है और माध्यमिक विद्यालय से केवल 78 मीटर की दूरी पर बना हुआ है और ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया गया है। मामले में जिसके नाम पर रजिस्ट्री नहीं है, उसे फर्जी ढंग से एनओसी प्रदान कर दिया गया है। पूरे मामले में जिस खसरा नंबर 181/5 में इसे बनाया गया है। उसका एनओसी दिया ही नहीं गया, बल्कि किसी अन्य खसरा नंबर का दिया गया है और जिस तारीख को एनओसी दिया गया उस तारीख को रजिस्ट्री ही नहीं हुई थी।

दिया फर्जी एनओसी

विधायक संगीता सिन्हा ने

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को बताया कि सारे नियमों को ताक में रखकर पटवारी और राजस्व निरीक्षक द्वारा फर्जी प्रतिवेदन दिया गया है और पंचायत के नाम से भी फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। यहां तक कि मामले में राजस्व निरीक्षक के ऊपर कार्रवाई की मांग भी की गई है। हर एक अधिकारी ने अपना काम नहीं किया है। इस पूरे मामले में बच्चों ने रैली भी निकाली, लेकिन जिम्मेदार मौन रहे अब राइस मिल बनकर तैयार भी हो चुका है।

कलेक्टर एसडीएम से हुई है शिकायत

आपको बता दें कि पूरे मामले में ग्रामीणों ने उसना राइस मिल के दुष्प्रभाव और प्रदूषण को देखते हुए कलेक्टर और एसडीएम को शिकायत किया गया है, लेकिन पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

एनओसी देकर घूमने निकले पंच सरपंच

विधायक ने सदन को बताया कि विधानसभा का यह सबसे बड़ा गांव है। यहां पर जब अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया तो बताया गया कि बसाहट से दूरी 900 मीटर है। लेकिन जब जांच की गई, तब पता चला कि मात्र 19 मीटर दूरी ही और यहां पर सड़क से दूरी डेढ़ किलोमीटर बताई गई है। लेकिन यहां पर दूरी मात्र 50 मीटर है, जब ग्रामीणों ने पूरे मामले का विरोध किया तो गांव के पंच और सरपंच गांव छोड़कर बाहर घूमने निकल गए।

सीएम साय को मोदी और शाह ने दी जन्मदिन की बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बुधवार को जन्मदिवस था। वे 60 साल के हो गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय बगिया के आदिवासी जनजाति बालक आश्रम में बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। उनके जन्म दिवस के अवसर पर लोग बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें बधाई दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोसल मीडिया ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के ओजस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वे छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। गरीबों और वंचित समुदायों के प्रति उनकी चिंता भी उल्लेखनीय है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं।

गृह मंत्री अमित शाह ने शोसल मीडिया ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा कि

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ में गरीब कल्याण व सुशासन के नए कीर्तिमान बनाएगी। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करता हूं। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उनके सुदीर्घ जीवन की मंगलकामना की। सीएम साय के जन्मदिवस के एक दिन पहले रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने स्कूली बच्चों को न्योता भोज दिया।

कृषि विवि में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की रणनीति का मसौदा तैयार

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र से नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु रणनीति तैयार करने के लिए आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु के पूर्व कुलपति डॉ राजेंद्र प्रसाद थे और अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल ने की। कार्यशाला के दौरान कृषि विश्वविद्यालय में नवीन शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया तथा इसके क्रियान्वयन हेतु रणनीति का मसौदा तैयार किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों के रूप में डॉ. एस. सुधाकर, प्राध्यापक तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, डॉ. के. गायकवाड़ प्राध्यापक, एन.आई.पी.बी., नई दिल्ली, डॉ. एस.के. दास, अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भुवनेश्वर, डॉ. एम. यासीन, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय सीहोर तथा डॉ. प्रमोद के. पाण्डेय, प्राध्यापक, कैलिफोर्निया

विश्वविद्यालय (संयुक्त राज्य अमेरिका) शामिल हुए। कार्यशाला में कुलपति डॉ. चंदेल ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणि वर्ष से नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने हेतु हर संभव प्रयास किये जाएंगे।

कार्यशाला में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित प्रावधानों को कृषि विश्वविद्यालय में लागू करने के संबंध में सुझाव दिये गये। इसके तहत कृषि महाविद्यालयों में मल्टिपल एन्ट्री एवं मल्टिपल एक्जिट के प्रावधान लागू करने का सुझाव दिया गया। इसके तहत कृषि महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को बीच में पढ़ाई छोडने पर सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। स्नातक पाठ्यक्रम में केवल एक वर्ष पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को कृषि में सर्टिफिकेट, दो वर्ष बाद पढ़ाई छोडने वाले विद्यार्थियों को डिप्लोमा तथा चार वर्ष अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को स्नातक उपाधि (डिग्री) प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही कृषि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए कौशल तथा उद्यमिता विकास एवं बाजार मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम शामिल करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा सक्षम मानव संसाधन विकास हेतु विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच तथा समस्या समाधान प्रवृत्ति विकसित करने पर भी बल दिया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा देश के कृषि विश्वविद्यालय में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं तथा कृषि विश्वविद्यालय में नवीन शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।

महतारी वंदन योजना : 72 लाख 74 हजार से अधिक महिलाओं ने भरा आवेदन

रायपुर। महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन भरने के लिए प्रथम चरण के अंतिम दिन भी महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। सभी जिले में पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर लगाए गए शिविरों में महिलाओं ने काफी बड़ी संख्या में आवेदन किया। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में अब तक 72 लाख 74 हजार से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रथम चरण में आवेदन करने के अंतिम दिन 20 फरवरी को प्रदेश में 1 लाख 78 हजार 514 महिलाओं ने आवेदन किया।

उल्लेखनीय है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष महिलाओं को 12 हजार रूपए दिये जाएंगे। प्रतिमाह

मिलने वाले एक हजार रूपए से महिलाएं अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकेंगी।

जिलेवार प्राप्त आवेदन- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक रायगढ़ जिले में 03 लाख 13 हजार 379, जांजगीर-चांपा में 02 लाख 88 हजार 939, बलरामपुर में 02 लाख 11 हजार 985 महिलाओं ने आवेदन की है। इसी प्रकार बलौदाबाजार में 03 लाख 49 हजार 681, कोण्डागांव 01 लाख 36 हजार 680, कवर्धा 02 लाख 54 हजार 876, सूरजपुर में 02 लाख 14 हजार 567, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 95 हजार 89, गरियाबंद में 01 लाख 94 हजार 662, बेमेतरा में 02 लाख 63 हजार 711, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से 01 लाख 89 हजार 163, रायपुर से 05 लाख 63 हजार 413, राजनांदगांव से 02 लाख 58 हजार 198, सक्ती से 02 लाख 11 हजार 282 महिलाओं ने महतारी वंदन योजना के तहत् आवेदन किया है। खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई से 1लाख 14 हजार 713, मुंगेली से 02 लाख 52 हजार 46, बालोद से 02 लाख 57 हजार 68, दंतेवाड़ा से 56 हजार 636, धमतरी से 2 लाख 73 हजार 19, जशपुर से 02 लाख 29 हजार 631, कोरबा से 03 लाख 8 हजार 363, कांकेर से 02 लाख 47 हजार 109, बस्तर से 01 लाख 90 हजार 357, दुर्ग में 04 लाख 21 हजार 701, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से 01 लाख 05 हजार 844, बिलासपुर से 04 लाख 12 हजार 716, सरगुजा से 02 लाख 39 हजार 129, कोरिया से 61 हजार 907, सुकमा से 52 हजार 324, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से 95 हजार 982, महासमुंद से 03 लाख 46 हजार 953, नारायणपुर से 27 हजार 503 और बीजापुर जिले से 35 हजार 465 महिलाओं से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

अमेठी का मैदान छोड़ने के मूड़ में नहीं हैं राहुल गांधी

अजय कुमार

कांग्रेस नेत्री और गांधी परिवार की बेटी प्रियंका वाड्रा गाँधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा पर कांग्रेस आलाकमान भले ही चुप्पी साधे हुए है, लेकिन राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने काफी कुछ साफ कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब अमेठी पहुंची तो लगे हाथ कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का संकेत देकर गाँधी परिवार की अमेठी-रायबरेली वाली सियासत को फिर जिंदा कर दिया है। यह दोनों वह संसदीय क्षेत्र हैं जिसका गांधी परिवार से काफी लगाव रहा है। जब कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में उखड़ गई तब भी अमेठी रायबरेली में उसकी जड़ें जमी रही थीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जरूर अमेठी से गाँधी परिवार का सफाया हो गया था लेकिन यहां कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है। गांधी परिवार भावनात्मक रूप से अपने आप को अमेठी से जोड़कर बड़ा उलटफेर करने की ताकत रखता है। खरगे ने राहुल गांधी की अमेठी से लोकसभा उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा नहीं की मगर अमेठी की जनता से यह जरूर कह दिया कि राहुल गांधी कल भी आपके साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इससे पूर्व सोनिया गांधी ने भी रायबरेली की जनता को लिखे भावनात्मक पत्र में अमेठी का जिक्र करके इसे गांधी परिवार के करीब बताया था। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने अमेठी से गांधी परिवार के करीबी रिश्ते को लेकर सोनिया गांधी के 26 साल पहले दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी भी अमेठी से दिल का करीबी रिश्ता होने की बात को आज दोहरा रहे हैं। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने के इरादों का साफ संदेश देते हुए खरगे ने इस संसदीय क्षेत्र की जनता से यह कहने से भी गुरेज नहीं किया कि भले ही क्षेत्र को कोई सांसद मिल सकता है, मगर राहुल गांधी जैसा इंसान उन्हें कहां मिलेगा। मगर इससे इत्तर अमेठी से चुनाव लड़ना गांधी परिवार के लिये अब आसान नहीं रह गया है। पिछले पांच वर्षों में अमेठी काफी बदल गया है। अमेठी की मौजूदा सांसद और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अमेठी की जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली है। खास बात यह रही कि मल्लिकार्जुन खरगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में जब अमेठी पहुंचे तो राहुल गांधी की मौजूदगी में वहां हुई एक जनसभा में अमेठी के रास्ते उत्तर प्रदेश के मैदान में कांग्रेस के डटे रहने का एलान किया गया। अमेठी वासियों के साथ गांधी परिवार के निकट रिश्तों का जिक्र करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक शायरी की पंक्तियों- 'अगर तलाश करे कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन हमको चाहेगा', के द्वारा राहुल के अमेठी के चुनावी रण में ताल ठोंकने की घोषणा की। खरगे ने यह भी कहा कि अमेठी को भले ही कोई सांसद मिल जाए मगर राहुल जैसा सहज और सहृदयी इंसान कहां मिल पाएगा। शायरी की इन पंक्तियों के बाद खरगे ने कहा कि अमेठी के लोग भी यही बोलते हैं और राहुल गांधी को चाहते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने को लेकर भले ही सीधे कोई टीका-टिप्पणी नहीं की लेकिन अमेठी और यहां के लोगों के साथ गहरे प्यार और जुड़ाव का इजहार करते हुए सदैव उनका आभारी रहने की बात कह पुराने रिश्ते की डोर को आगे बढ़ाते रहने का संदेश दिया। अमेठी से रिश्ते की बुनियाद नई नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। खैर, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राहुल गांधी और उससे पहले सोनिया गांधी के रिश्ते की बुनियाद अमेठी से नई नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। इसका संदेश देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीति में आने के बाद 1998 में पहली बार अमेठी आयी सोनिया गांधी के पूरे बयान को पढ़ा। इसमें सोनिया ने कहा था- 'मेरे मन में अमेठी के लोगों के प्रति अटूट प्रेम और आदर है।

राजनीति के शोर में संदेशखाली की आवाज

डॉ. आशीष वशिष्ठ

बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल का संदेशखाली सुर्खियों में बना हुआ है। संदेशखाली से जो खबरें छन-छनकर बाहर आ रही हैं, वो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को व्यथित कर सकती हैं। संदेशखाली पर जितनी रपटें और विश्लेषण सामने आए हैं, उनके मद्देनजर आश्चर्य होता है कि 2011 से वहां 'दरिंदों' के अत्याचार, यौन उत्पीड़न और भूमि पर जबरन कब्जों के सिलसिले जारी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें झूठ करार दे रही हैं। जो जानकारी आई उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि संदेशखाली में मध्ययुगीन गुलाम प्रथा जिंदा है।

संदेशखाली का पूरा मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई के बाद लोगों के सामने आया है। बीती 5 जनवरी, 2024 को ईडी के अधिकारियों ने राशन भ्रष्टाचार मामले में संदेशखाली के सरबेड़िया में तृणमूल नेता शेख शाहजहां से पूछताछ करने पहुंचे हुए थे। तृणमूल के गुंडों की मदद से न सिर्फ नेता शाहजहां शेख फरार हो जाने में कामयाब रहा, बल्कि इस दौरान सरकारी अधिकारियों पर भी हमले भी किए गए थे। इसके बाद से ही स्थानीय लोगों ने अपनी आवाज तेज कर दी और खुलकर सामने आ गए। जो कुछ भी उनके द्वारा बताया गया, वह 21वीं सदी में अकल्पनीय है।

शाहजहां शेख और उसके गुर्गे महिलाओं को अपनी निजी संपत्ति मानकर उठा ले जाते रहे और तृणमूल कार्यालय में रखकर उनका यौन शोषण कर छोड़ देते थे। विवाहित महिला के पति को भी ये कहा जाता कि उसकी पत्नी पर पहला अधिकार शेख का है। किसी भी सुंदर महिला को जबरन उठाकर ले जाना और उसका यौन शोषण करना संदेशखाली में आम बात थी। जब महिलाओं से पूछा गया कि वे इस अत्याचार के विरुद्ध अब तक खामोश क्यों रहीं तो उनका उत्तर था कि शाहजहां जब ईडी के डर से फरार हुआ तब जाकर उनमें साहस आया। वह लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा करने और उनकी मजदूरी छीनकर आतंकित करने का काम करता रहा किंतु तृणमूल कांग्रेस

से जुड़ा होने की वजह से उसका हौसला बुलंद था।

ईडी की छापेमारी के बाद संदेशखाली महिला सशक्तीकरण का जीवंत उदाहरण बन गया है। लेकिन महिला होने के बावजूद ममता बनर्जी अभी तक अपनी पार्टी के कुख्यात नेता पर लग रहे आरोपों पर ध्यान देने के बजाय ये शिगूफा छोड़ रही हैं कि संदेशखाली आरएसएस का प्रभावक्षेत्र है। महिलाओं पर उनके साथ हुए बलात्कार को साबित करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। विवाद बढ़ने के बाद 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने संदेशखाली का दौरा किया। यहां की महिलाओं से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने मीडिया से कहा, ''मैंने संदेशखाली की माताओं और बहनों की बातें सुनी. मुझे विश्वास नहीं हुआ कि रबिन्द्र नाथ टैगोर की धरती पर ऐसा भी हो सकता है।'' राज्यपाल के बयान से स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की फैक्ट-फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट से भी संदेशखाली के हालात की भयानकता उजागर हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'गांव की महिलाओं से जुटाई गई गवाहियां परेशान करने वाली हैं, जो वहां व्यापक भय और व्यवस्थित दुर्व्यवहार की एक भयावह तस्वीर सामने लाती हैं।' इसके मुताबिक, 'पीड़िताओं ने पुलिस अधिकारियों और तृणमूल कांग्रेस के लोगों की ओर से की गई शारीरिक और यौन हिंसा की वारदातों का जिक्र किया।' इससे लगता है कि शाहजहां शेख ने संदेशखाली में अपने गुनाहों का जो साम्राज्य कायम किया था, उसमें पुलिस भी सक्रिय तौर पर शामिल थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस गांव की जिस महिला ने भी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चारों ओर से दबाव पड़ने पर दिखावे के लिए कुछ छुटभैये किस्म के तृणमूल नेताओं को पुलिस ने जरूर पकड़ा है किंतु जो लोग संदेशखाली के हालात का जायजा लेने जा रहे हैं उनको भी रोकने की करवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा किए जाने से साफ है कि ममता सरकार को महिलाओं के मान-सम्मान से अधिक अपनी पार्टी के नेताओं की चिंता है। पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने मुस्लिम तुष्टिकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। बंगाल में 27 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। ममता बनर्जी इनके तुष्टिकरण से ही सत्ता में बनी हुई हैं और इस्लामी एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अपने धार्मिक रीति-रिवाज, पर्व-त्योहार मनाने तक की स्वतंत्रता नहीं रह गई है।

वस्तुस्थिति ये है कि वामपंथी सरकार के राज में जो गुंडे आतंक का पर्याय थे वे सभी सत्ता परिवर्तित होते ही तृणमूल कांग्रेस में आ गए। परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल की स्थिति आसमान से टपके खजूर पर अटके वाली होकर रह गई। पहले जो लूटपाट वामपंथी पार्टी का कैडर करता था, वही अब तृणमूल कार्यकर्ता बन चुके असामाजिक तत्व धड़ल्ले से करते हैं। चूंकि पुलिस उनके क्रियाकलापों पर रोक नहीं लगाती लिहाजा जनता भी भयग्रस्त है। संदेशखाली की घटना पहली नहीं है। बीते कुछ सालों में यह राज्य अराजकता के शिकंजे में फंस गया है। चूंकि कांग्रेस और वामपंथी पूरे तौर पर हाशिए पर आ चुके हैं इसलिए भाजपा ही पश्चिम बंगाल में विकल्प के रूप में उभर रही है। संदेशखाली की लड़ाई में भी वही पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी हुई है। हालांकि लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ममता सरकार के विरुद्ध आवाज उठाया करते हैं किंतु जिस इंडिया गठबंधन में तृणमूल भी शामिल है, उसकी ओर से संदेशखाली में हुए अत्याचार के विरुद्ध कुछ न कहा जाना चौंकाता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से भी ममता बनर्जी की सरकार का वैसा विरोध नहीं हुआ जैसा अपेक्षित था।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा है कि संदेशखाली में आरएसएस का अड्डा है और वही औरतों को उकसा और बरगला रहा है। यदि संघ किन्हीं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, तो मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? लेकिन ममता बनर्जी ने इस कांड पर अब तक जिस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया वह शर्मनाक है। क्या यह संभव हो सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जानकारी ही न हो कि उनका 'सिंडिकेट' कहां है? ममता-राज के दौरान तृणमूल के भीतर ही ऐसा सिंडिकेट बना दिया गया है, जो ज्यादातर हिंदू आबादी पर ही दरिंदगी दिखाते हैं। पुरुषों को जान से मार देने की धमकियां भी देते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान इसी सिंडिकेट ने भाजपा के खिलाफ 273 घटनाएं की थीं। कई कार्यकर्ताओं को भी मार दिया गया था। यह गुंडई पंचायत चुनावों में सरेआम कहर ढहाती रही है। क्या एक महिला मुख्यमंत्री का शासन ऐसा भी हो सकता है कि दरिंदे खुलेआम हत्याएं और अत्याचार कर सकें? इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का रवैया भी निराशाजनक है। जब किसी स्थान की दर्जनों महिलाएं उन पर हुए अमानुषिक अत्याचार की जानकारी सार्वजनिक रूप से दे रही हों तब तो मुख्यमंत्री को खुद उनसे मिलकर अपराधियों को सजा दिलवाने की पहल करनी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत वे इसे राजनीतिक मोड़ देकर अपनी पार्टी के साथ जुड़े समाज विरोधी तत्वों को बचाने में जुटी हुई हैं। बेहतर होता कि कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन में शामिल अन्य दलों का संयुक्त प्रतिधिमंडल संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं की बात सुनकर ममता बनर्जी को कठघरे में खड़ा करता किंतु वोटों की राजनीति के कारण महिलाओं के अपमान पर भी अधिकतर पार्टियां मौन साधे बैठी हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं इसलिए देखना ये होगा कि इतना गंभीर मुद्दा कहीं राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और शोर—शराबे में दबकर न रह जाए। आरोपियों का कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो नजीर बनें।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-12)

गतांक से आगे...

जो किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष आदि के भाव नहीं रखता है, जो न किसी की इच्छा-आकांक्षा करता है। जो केवल प्रारब्धवश प्राप्त भोगों का उपभोग करने वाला है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसने सांसारिक विषयों की प्राप्ति की कामना को त्याग दिया है, जो चित्त में रहते हुए भी चित्तरहित हो गया है, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है। जो पुरुष जगत् के सम्पूर्ण अर्थ जाल के बीच में प्रतिष्ठित होकर भी उससे पराये धन से अलग रहने वाले धर्मात्मा के सदृश अनासक्त रहता है, निश्चय ही वह आत्मा में ही परमात्मतत्त्व की अनुभूति करने वाला महान् पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है। वह पुरुष अपने शरीर के काल-कवलित हो जाने के पश्चात् जीवन्मुक्त स्थिति का परित्याग करके गतिहीन पवन के सदृश विदेहमुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में जीव की न तो उन्नति होती है और न ही अवनति तथा उसका विनाश भी नहीं होता। उसकी वह अवस्था सत-असत् से परे होती है और वह किसी के दूरस्थ-समीपस्थ भी नहीं होता।

विदेहमुक्ति गम्भीर एवं स्तब्ध अवस्था को कहते हैं। उस अवस्था में न सर्वत्र प्रकाश व्याप्त होता है और न ही अन्धकार। उसमें नामविहीन एवं अभिव्यक्त न होने वाला एक तरह का सत् तत्त्व अवशिष्ट रहता है। वह शून्य एवं साकार भी नहीं होता है। दृश्य एवं दर्शन रूप भी नहीं होता है। उसमें ये भूत एवं पदार्थ समूह भी नहीं होते हैं। केवल वह सत् अन्तरहित स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। वह ऐसा आश्चर्ययुक्त तत्त्व होता है कि जिसके रूप का निर्देशन नहीं किया जा सकता है। उसकी आकृति एवं प्रकृति पूर्ण से भी पूर्णतर होती है। वह न सत् होता है और न असत् तथा सत-असत् दोनों भी नहीं होता। वह भाव एवं भावना से परे होता है।

क्रमशः ...

गांधीजी के साथ साए की तरह साथ खड़ी रहीं कस्तूरबा गांधी

अनन्या मिश्रा

कस्तूरबा गांधी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में 11 अप्रैल 1869 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता और कस्तूरबा के पिता करीबी दोस्त थे। ऐसे में मात्र 7 साल की उम्र में उनकी गांधीजी से शादी तय कर दी गई थी। वहीं मात्र 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी।

महात्मा गांधी का नाम बच्चा-बच्चा जानता है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी गांधीजी की लोकप्रियता पाई जाती है। उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनके द्वारा सिखाए गए सत्य और अहिंसा मार्ग के बारे में तो आप सब ने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी, बापू और राष्ट्रपिता बनने के पीछे एक महिला का बेहद अहम

रोल है। अगर यह महिला न होती तो शायद आज गांधी जी महात्मा न होते। आपको बता दें कि इन्होंने अपना पूरा जीवन गांधीजी के नाम कर दिया। हरपल उनके साथ साए की तरह खड़ी रहीं और उनका मनोबल बढ़ाती रहीं। आपको बता दें कि यह महिला और कोई नहीं बल्कि महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी हैं। एक सपंन्न घराने की बेटी गांधीजी के साथ पग-पग पर उनका साथ देती रही। आज ही के दिन यानि की 22 फरवरी 1944 को देश की बा यानि की कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था।

कस्तूरबा गांधी का जीवन कठिन संघर्षों में बीता। संपन्न परिवार में जन्मी कस्तूरबा गांधी नाजों से पली-बढ़ी थीं। लेकिन उन्होंने शादी के बाद काफी संघर्ष देखें। उन्होंने कभी भी गांधीजी से पति और पिता के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नहीं कहा। जहां गांधीजी ने अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया तो वहीं बा ने कभी उनसे शिकायत नहीं की। जब गांधीजी स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल गए तो कस्तूरबा गांधी हर पल उनके साथ खड़ी रहीं।

कस्तूरबा गांधी केवल महात्मा गांधी की पत्नी ही नहीं बल्कि हर देशवासी की बा बन गईं। उनके कामों और संघर्षों के कारण उन्हें यह उपाधी दी गई। भले ही दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन महात्मा गांधी ने छेड़ा था। लेकिन पहली बार इस पर कस्तूरबा गांधी का ही ध्यान गया था। जब कस्तूरबा गांधी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें 3 महीने की जेल हो गई थी। लेकिन जेल में भी वह कैदियों का दुख-दर्द बांटा करती थीं। उनके सेवा भाव को देखते हुए लोग उन्हें बा कहकर पुकारने लगे।

गांधीजी के उपवास के दौरान, धरना प्रदर्शन के दौरान कस्तूरबा गांधी उनकी सच्चे मन से सेवा करती थीं। आपको बता दें कि कस्तूरबा गंभीर ब्रोंकाइटिस रोग से पीड़ित थीं। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि गांधी जी साथ स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में उनकी तबियत तेजी से बिगड़ने लगी। बता दें अगस्त 1942 में गांधीजी को कस्तूरबा के साथ पुणे के आगाखान पैलेस में भी नजर बंद किया था। इसी महल में कस्तूरबा गांधी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। उनके निधन के बाद इसी भवन में उनकी समाधि भी बनाई गई।

चीन में कंपनियां बना रही अपनी मिलिशिया यूनिट

अभिनय आकाश

कहा जाता है कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर की होती है। ये मौखिक विवरण की तुलना में इसके अर्थ या सार को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। उस वाक्या को भला कौन भूल सकता है जब रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ 62 वर्षीय येवगेनी प्रिगोझिन ने दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति रूस के प्रमुख नेता को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करने की कसम खाते नजर आए थे। प्राइवेट आर्मी की जब भी बात आती है तो रूस का वैगनर ग्रुप और अमेरिका की एकेडमी दो ऐसी जानी मानी कंपनियां है जो हाल के सालों में विवादों में रही हैं। वहीं एक मुल्क ऐसा भी है जो हमारे पड़ोस में है, ये मुल्क जिसने कोरोना के मामले में लापरवाही बरती और पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जो पूरी दुनिया में कभी कारोबार फैलाने के नाम पर तो कभी किसी मदद को देने के नाम पर घुसपैठ कर चुका है। जो अपने यहां के अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार करता रहता है। वो मुल्क जो आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा है। लेकिन 1970 के दशक के बाद एक नई चीन की ओर फिर से उसने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। हम बात चीन की कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन अपने पुराने ढर्रे पर लौट रहा है। चीन की कंपनियां अपनी-अपनी वॉलंटियर आर्मी बनाने में जुटी है। 1970 के दशक में ये चीन में बेहद ही आम थी। देश के कई सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों और एक निजी फर्म ने पिछले वर्ष में घरेलू लड़ाकू बलों की स्थापना की है।

निजी इकाइयों को पीपुल्स आर्म्ड फोर्सेज (पीएएफ) के रूप में जाना जाता है। वे उन नागरिकों से बने हैं जो अपनी नियमित नौकरी जारी रखते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी चीन की सेना के लिए एक आरक्षित बल के रूप में कार्य करते हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीपुल्स आर्म्ड फोर्सेज से युद्ध के दौरान सहायता, राष्ट्रीय आपदाओं के दौरान संचालन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद जैसे मिशनों के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। एफटी की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि ये निजी सेनाएं नागरिक सुरक्षा गतिविधियां

चलाती हैं और सैन्य भर्ती, पदोन्नति और प्रशिक्षण में योगदान देती हैं। हालाँकि, इन बलों के सदस्य अभी चीन के बाहर काम नहीं करते हैं। वे काफी हद तक अमेरिका के नेशनल गार्ड की तरह हैं, एक राज्य-आधारित बल जो अमेरिकी सेना के निजी लड़ाकू रिजर्व के रूप में कार्य करता है। पिछले साल से चीन के निजी मिलिशिया में वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2023 में चीनी रक्षा मंत्रालय ने इन इकाइयों को राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) में शामिल करने पर जोर देने की पुष्टि की। धिकांश निजी बल एसओई द्वारा स्थापित किए जाते हैं, दिसंबर में यिली ग्रुप अपनी इकाई स्थापित करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। दुनिया के शीर्ष डेयरी उत्पादकों में से एक, कंपनी को राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन होहोट में स्थानीय सरकार, जहां यह स्थित है।

1949 में पार्टी के सत्ता हासिल करने के बाद सशस्त्र बल समूहों ने कम्युनिस्ट पार्टी को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपने पैर जमाने में मदद की। उन्होंने कम्युनिस्ट विरोधी विद्रोहों पर नकेल कसी और सभी को पार्टी लाइन का पालन करने के लिए बाध्य किया। चेंग ने वीओए को बताया कि कभी-कभी ये समूह ग्रामीणों और कारखाने के श्रमिकों के खिलाफ लाठी, बंदूक और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, जो अभी भी किया जा सकता है। 6 मई 1966 को माओ ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की जिसे कल्चरल रिव्यूलूशन के नाम से भी जाना जाता है। उसी दिन '16 मई की सूचना' नाम से एक विज्ञप्ति जारी की गयी। उसमें कहा गया था कि विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, कला, समाचार, पुस्तक-प्रकाशन इत्यादि कई क्षेत्रों का नेतृत्व अब 'सर्वहारा वर्ग के हाथों में नहीं रह गया है. उन्हें चला रहे सारे बुद्धिजीवी साम्यवाद-विरोधी हैं, जनता के शत्रु प्रतिक्रांतिवादियों का ढेर हैं। माओ लिखित 'लाल पुस्तक' लिये बच्चे और छात्र सांस्कृतिक क्रांति के 'लाल रक्षक' (रेड गार्ड) कहलाते थे। हर दिन हज़ारों-लाखों की संख्या में गांवों-शहरों की सड़कों पर निकल कर माओ के कथित 'शत्रुओं' को ढूंढते हुए वे उन पर टूट पड़ते थे। 18 जून 1966 को विश्वविद्यालयों के 60 वरिष्ठ प्रोफ़ेसरों की अपराधियों जैसी सुनवाई के बाद सड़कों पर दौड़ा-दौड़ा कर उन्हें लातों-मुक्कों से मारा गया। चीन की ये सांस्कृतिक क्रांति 9 सितंबर 1976 को माओ की मौत के साथ खत्म हो गई।

जैसे-जैसे चीन की अर्थव्यवस्था धीमी होती जा रही है, वहां की जनता में सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है। ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने के कारण विदेशों में भी संघर्ष की चिंता है। विश्लेषकों का कहना है कि इन कॉर्पोरेट ताकतों की स्थापना मुद्दों पर बीजिंग की चिंताओं को उजागर करती है। इसे महामारी के बाद समाज पर कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ मजबूत करने के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रयासों के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। 2023 में चीन की इकॉनमी 5.2 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी। लेकिन देश की इकॉनमी को कई मोर्चों पर चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर संकट में है। युवा बेरोजगारी चरम पर है। डिफ्लेशन का दबाव है। कॉरपोरेट डिफॉल्ट बढ़ रहा है और स्थानीय सरकारें कर्ज में डूबी हैं।

चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने अक्टूबर 2023 में कहा था कि पीएएफडी बढ़ाने का प्रयास राष्ट्रीय रक्षा के लिए चीन के पूरे देश के दृष्टिकोण का हिस्सा था और मिलिशिया बड़े पैमाने पर लामबंदी से लेकर प्रतिक्रिया तक हर चीज के लिए उपलब्ध हैं। चीन की राज्य समाचार एजेंसी शिन्हुआ द्वारा दिए गए एक बयान में, उन्होंने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों में कॉर्पोरेट ब्रिगेड की स्थापना राष्ट्रीय रक्षा दायित्वों को पूरा करने और राष्ट्रीय रक्षा निर्माण को मजबूत करने के लिए आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि स्वामित्व वाले उद्यमों के भीतर पीपुल्स सशस्त्र बल इकाइयां राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली का एक घटक है, यह उद्यमों के भीतर पार्टी का सशस्त्र कार्य विभाग है, साथ ही उद्यमों के भीतर सरकार की भर्ती शाखा भी है। कड़े कोविड-19-संबंधित प्रतिबंधों को विरोध प्रदर्शनों और जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा, जो कि कम्युनिस्ट राष्ट्र में असामान्य है। जब से चीन संपत्ति मंदी का सामना कर रहा है और अपस्फीति, युवा बेरोजगारी और कॉर्पोरेट डिफॉल्ट से जूझ रहा है तब से प्रदर्शन और बढ़ गए हैं। श्रमिकों के विरोध प्रदर्शनों पर नज़र रखने वाली हांगकांग स्थित गैर-लाभकारी संस्था, चाइना लेबर बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में श्रमिक हड़तालें बढ़कर 1,794 हो गई हैं, जो एक साल पहले दर्ज की गई 830 से दोगुनी से भी अधिक है। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस में चीनी राजनीति के फेलो नील थॉमस ने सीएनएन को बताया कि कॉर्पोरेट मिलिशिया की वापसी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आर्थिक विकास को बेहतर ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता पर शी के बढ़ते फोकस को दर्शाती है क्योंकि देश अधिक कठिन भविष्य का सामना कर रहा है। निजी सेनाएँ कम्युनिस्ट पार्टी को विरोध प्रदर्शनों और कर्मचारियों की हड़तालों को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने में मदद कर सकती हैं। पूर्व और दक्षिण एशिया दोनों में अमेरिकी राजनयिक के रूप में भी काम करने वाले सेवानिवृत्त अमेरिकी मरीन कर्नल ग्रांट न्यूशम ने कहा कि निजी सेनाएं सत्ता संभालने के बाद से शी जिनपिंग के नियंत्रण को मजबूत करने और मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा हैं। उन्होंने वॉयस ऑफ अमेरिका (वीओए) को बताया, यह नियंत्रण अंततः हिंसा और धमकी के संभावित या वास्तविक उपयोग पर निर्भर है। एसओई में इन सशस्त्र बल इकाइयों के होने से नियंत्रण बढ़ता है और नियंत्रण मजबूत होता है, और हिंसा का मनोवैज्ञानिक खतरा होता है।

आज का इतिहास

1949 सिनसिनाटी गार्डन सिनसिनाटी शहर में खोला गया।
1956 एल्विस प्रेस्ली ने हार्टब्रेक होटल में पहली बार संयुक्त राज्य संगीत चार्ट में प्रवेश किया।
1958 मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर और सीरियाई राष्ट्रपति शुकरी अल-क्वातली ने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने के लिए एक संघ संधि पर हस्ताक्षर किए।
1979 यूनाइटेड किंगडम ने सेंट लूसिया को स्वतंत्रता प्रदान की।
1980 अफगानिस्तान में सैनिक शासन लागू होने की घोषणा हुई।
1980 न्यूयॉर्क के लेक प्लासीड में शीतकालीन ओलंपिक में, यूनाइटेडस्टेट्स आइस हॉकी टीम ने सोवियत संघ को हरा दिया एक अप्रत्याशित जीत में बर्फ पर चमत्कार के रूप में जाना जाता है।
1983 नाटक मूस मर्डर्स उसी रात न्यूयॉर्क सिटी के यूजीन ओ नील थियेटर में खोला और बंद किया गया, जो वेवनेस का मानक बन गया, जिसके खिलाफ सभी ब्रॉडवे थिएटर विफलताओं को आंका जाता है।
1995 अल्जीयर्स पुलिस द्वारा कम से कम 99 जेल दंगाइयों को मार दिया गया।
1995 अमेरिकी राष्ट्रपति बिलक्लिंटन द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के तहत कोरोना जासूस उपग्रह कार्यक्रम द्वारा खींची गई तस्वीरों को हटा दिया गया था।
1996 अभिनेत्री हेले बेरी ने डेविड जस्टिस से तलाक लिया।
1997 स्कॉटलैंड के रोसलिन संस्थान में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पहली बार किसी स्तनधारी जीव से निकाली गई कोशिका से क्लोन बनाने की घोषणा की।
1997 एलपीजीए कप नूडल्स हवाईयन लेडीज ओपन को अन्निका सोरेनस्टैम ने जीता।
1997 स्कॉटलैंड में द रोसलिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने डॉली नामक एक क्लोन भेड़ के बच्चे के जन्म की घोषणा की, तथ्य यह है कि इस तथ्य के सात महीने बाद, एक वयस्क कोशिका से बेजान होने का पहला स्तनपायी है।
1998 1998 शीतकालीन ओलंपिक जापान में नागानो में आयोजित किया गया।
1998 18 वें शीतकालीन ओलंपिक खेल जापान के नागानो में बंद हुए।
2006 iTunes का गाना Apple स्टोर द्वारा 1 बिलियन में बेचा गया था।
2006 कम से कम छह पुरुषों ने ब्रिटेन की सबसे बड़ी नकदी डकैती का मंचन किया, जो कि केंट के टोनब्रिज में एक सिक्यूरिटीज डिपो से बैंक नोटों में £ 53,116,760 चोरी कर रहा था।
2010 ग्रीस और यूरोपीय संघ द्वारा ग्रीस के लिए 20 – 25 बिलियन यूरो की वित्तीय सहायता योजना की योजना बनायी गयी।

एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं

डॉ. आशीष वशिष्ठ

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान के तहत देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है। लेकिन, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कानून की गारंटी के लिए आंदोलनरत किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें मंगवाने के पक्षधर नहीं दिखते। सरकार बातचीत के माध्यम से समस्या सुलझाना चाहती है। लेकिन किसान नेताओं के तेवरों और मांगों की लंबी सूची के दृष्टिगत इस बात की संभावना न्यून है कि बातचीत से ये मसला निपटेगा। वास्तव में किसान नेता भी जानते हैं कि एमएसपी कानून की गारंटी देना इस सरकार तो क्या किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है।

किसानों के असली इरादों को उनकी तैयारियों को देखकर समझा जा सकता है। जिस तरह ट्रैक्टर ट्रालियों में महीनों का राशन और दूसरा जरूरी सामान लेकर वो घरों से निकले हैं, उससे साफ है कि उनकी मंशा समझौते की नहीं, टकराव की है। वो चाहते हैं कि गलती से शासन प्रशासन के हाथों कोई ऐसा काम हो जाए, जिससे वो और उनका पूरा इको सिस्टम सरकार को किसान विरोधी साबित कर सके। ये सारी कवायद चुनाव से पहले माहौल खराब करने और सरकार की छवि को ठेस पहुंचाने की दिखाई देती है।

किसान समस्या का हल चाहते तो बातचीत में विश्वास करते। वो तो दिल्ली की तरफ हजारों की भीड़ लेकर ट्रैक्टर ट्रालियों, गाड़ियों और अन्य साधनों से दिल्ली की ओर ऐसे बढ़े मानो उन्हें किसी विदेशी सरकार से निर्णायक संघर्ष करना है। किसान नेता जब मीडिया या किसी सार्वजनिक मंच से बोलते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो केंद्र सरकार उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मीडिया से बातचीत के समय किसान नेताओं और उनके समर्थकों की भाषा, बॉडी लैग्वेंज और भाषणों की टोन ऐसी होती हैं मानो किसी दुश्मन देश की सरकार को वो चेतावनी दे रहे हों। करोड़ों नागरिकों द्वारा निर्वाचित सरकार, जो बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, उसके प्रति किसान नेताओं का अनादर का भाव कदम कदम पर दिखाई देता है।

किसान नेता अपने आंदोलन को अराजनीतिक बताते हैं। लेकिन राजनीतिक संगठनों के साथ उनके रिश्ते जगजाहिर हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन तो बहाना है- असली काम तो मोदी सरकार को हटाना है। लोगों में चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर बिना राजनीतिक दलों के समर्थन के इतना बड़ा आंदोलन इतनी जल्दी कैसे खड़ा हो सकता है। 2020 में तीन कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के 34 किसान संगठन विरोध कर रहे थे, जबकि यह आंदोलन मात्र कुछ किसान संगठनों द्वारा ही किया जा रहा है। तो क्या यह सही है कि इस बार का आंदोलन किसी विशेष उद्देश्य से हो रहा है?

भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल इस बार किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरे हैं। जिस तरह पिछली बार गुरुनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत थे इस बार डल्लेवाल हैं। उनके मुंह से किसान आंदोलन की सच्चाई निकल गई है। डल्लेवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया था, उसे नीचे लाना है। आंदोलन में शामिल पंजाब के किसान नेता तेजवीर सिंह का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो किसान आंदोलन के जरिए देश की सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं वो किसान आंदोलन को विपक्ष की लड़ाई लड़ने वाला भी बता रहे हैं। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं किसान नेताओं को एक बात समझाई गई है कि ये लड़ाई किसानों के अधिकारों और एमएसपी की गारंटी के लिए नहीं है बल्कि इन मुद्दों के नाम पर सरकार को ही बदलना है।

यही नहीं किसान आंदोलन को कवर कर रहे बहुत से यूट्यूबरों, मीडिया हाउसेस के वीडियो देखने को मिल रहे हैं जिन्हें देखकर आप यही कह सकते हैं कि किसान आंदोलन भ्रमित है या गलत लोगों के हाथ में है। बहुत से किसान इंडिपेंडेंट पंजाब या खालिस्तान की बात करते हुए मिलते हैं। कुछ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए मिल जाते हैं। इन किसानों के मन में एमएसपी पर गारंटी की डिमांड कम, केंद्र सरकार को बदलने का जज्बा काफी है। इनमें से कुछ में नरेंद्र मोदी के लिए इतनी नफरत भरी हुई है जैसे किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने विरोधी दलों के नेताओं के बारे में रखता है। बल्कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में भी अपने विरोधी दल के नेता के लिए मरने-मारने की बात नहीं होती। यहां तो किसान मरने-मारने की बात भी कर रहे हैं। पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रोकने की जिम्मेदारी लेने वाले संगठन भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी संगठन भी इस आंदोलन में शामिल है।

आंदोलन शुरू होने से 2 दिन पहले जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट किसान आंदोलन को समर्थन करते आ गया था उससे भी इस संदेह को बल मिला कि यह आंदोलन किसानों के अधिकार के लिए नहीं बल्कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ज्यादा है। कांग्रेस नेता रमनदीप सिंह मान पर आरोप है कि वो कांग्रेस और किसान नेताओं के बीच कड़ी का काम कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य के हैंडल ने उनके कई ट्वीट्स की कड़ी का थ्रेड बनाकर अपने हैंडल पर डाला हुआ है। इस थ्रेड से पता चलता है कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने किस तरह रमनदीप सिंह के साथ मिलकर किसान आंदोलन को खड़ा किया। जब चार साल पहले तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी को लगभग 13 महीने तक बंधक बनाए रखा गया था। धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के बहाने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किसान संगठनों की ओर से बनाए गए माहौल का ही नतीजा था कि केंद्र सरकार को उन तीन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, जिन्हें कृषि और कृषक समुदाय के लिए क्रांतिकारी माना जा रहा था।

सच्चाई यह है कि पिछली सरकारों ने जो कुछ किसानों की भलाई के लिए किया, वर्तमान सरकार ने उससे बढ़कर ही किया है। आंकड़ें इसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। ये भी सच्चाई है कि किसानों की भलाई के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी भी है। असल में, जब आंखों में विरोधी चश्मा चढ़ा हो और दिमाग में रटी रटाई स्क्रिप्ट तैर रही हो तो बातचीत से मामला हल कहां होने वाला है? सरकार चाहे जितने भी उपाय और मजबूरियां बता दे, किसान नेताओं को तो अपनी बात पर अड़े रहना है। शायद उनके राजनीतिक आकाओं की ऐसी ही मंशा होगी।

किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। पिछले सात दशक से जिस तरह की कृषि नीति देश में अपनायी गयी है, उन नीतियों से किसानों की स्थिति तो नहीं सुधरी है, न ही उनको उनकी उपज का वाजिब दाम ही मिल पाता है। लेकिन किसानों के ही फ़सलों से कृषि तंत्र पर क़ब्ज़ा जमाए बिचौलियों और कारोबारियों की आर्थिक सेहत हमेशा ही बल्ले-बल्ले रही है। कृषि क्षेत्र में सुधार और बिचौलियों को सिस्टम से बाहर करने के लिए ही सरकार तीन नये कृषि कानून लेकर आई थी। लेकिन ये भ्रम फैलाया गया कि नये कानून किसान विरोधी हैं। सरकार ने भी दबाव में आकर कानून वापस ले लिये। जानकारों का मानना है कि, नये कृषि कानून लागू हो गये होते तो किसानों की कई समस्याओं का हल स्थायी तौर पर हो जाता। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, उनका जीवन सुधरे और वो भी पूरे मान सम्मान के साथ जीवन बिताएं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। किसानों को भी तनातनी और राजनीति छोड़कर बातचीत से मसला हल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। हिंसा और उपद्रव से किसानों की छवि तो खराब होती ही है, देश के साधनों और संसाधनों का नुकसान होता है और आम नागरिकों को भी परेशानियां पेश आती हैं। सरकार को सहानुभूति पूर्वक किसानों की व्यावहारिक मांगों को स्वीकार करना चाहिए। शांति और सद्भाव का माहौल ही किसी देश के विकास को गति प्रदान करता है।

इस वक्त संकट में मोदी सरकार नहीं, बल्कि कांग्रेस है!

अभय कुमार दुबे

मुझे लगता है कि किसान आंदोलन का दूसरा उभार दिल्ली की सीमाओं पर लगाए गए कंक्रीट और कंटीले तारों के बेरिकेडों की अभेद्यता के समान मजबूर हो चुका है। अगर किसान दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे तो केंद्र सरकार पर कोई दबाव पैदा नहीं होगा। इसलिए पूरी संभावना है कि वार्ता के तीसरे-चौथे दौरों के बाद कोई बीच का रास्ता निकल आएगा जिनके तहत किसानों की वापसी हो जाएगी। मुझे यह भी लगता है कि चुनावी बॉन्डों की स्कीम को गैरसंवैधानिक ठहराये जाने से एक बहस जरूर पैदा हुई है, लेकिन उससे केंद्र सरकार पर कोई संकट नहीं आया है।दरअसल संकट में सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस है। क्या साठ साल तक सत्ता में रहने वाली केवल दस साल के भीतर ही इस दुर्गति तक पहुंचनी चाहिए? कांग्रेस की इस बुरी हालत के कई कारण हैं। भाजपा और संघ परिवार द्वारा राजनीतिक विमर्श को पूरी तरह से बदल देना इसका एक प्रमुख कारण है। साठ के दशक से ही धीरे-धीरे विभिन्न समुदायों को एक-एक करके कांग्रेस का साथ छोड़ते देखना भी इसका एक कारण है। क्षेत्रीय ताकतों के उदय के कारण कांग्रेस के प्रभाव-क्षेत्र का सिकुड़ते जाना इसका अन्य कारण है। लेकिन, मैं समझता हूं कि इनके साथ-साथ और इन सबसे ऊपर कांग्रेस के तेज पराभव का सबसे बड़ा कारण है नेतृत्व की कमजोरी और विफलता। दृष्टिहीनता, रणनीतिहीनता, नए तत्वों के समावेश में नाकामी, संगठन के कामकाज को गंभीरता से न लेना, एक परिवार के सदस्यों की कथित प्रतिभा पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करना, ये हैं कुछ समस्याएं जिनका कांग्रेस सामना कर रही है। पार्टी के पास कोई भी दूरगामी नजरिया नहीं है। सोनिया गांधी तो 2004 में पार्टी को 'एकला चलो रे' से निकाल कर गठजोड़ युग में ले जा कर अपनी नेतृत्व-क्षमता साबित कर चुकी हैं। लेकिन, उनकी दोनों संतानों ने बार-बार स्वयं को राजनीतिक क्षमता से वंचित साबित किया है। राहुल और प्रियंका के मुकाबले अगर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन और जनगमोहन रेड्डी जैसे नेताओं को देखा जाए तो वे अधिक कुशल प्रतीत होते हैं। इसी तरह कांग्रेस में भी रेवंत रेड्डी जैसे युवा नेतृत्व का उभार हुआ है। नए अध्यक्ष (जो अब इतने नए भी नहीं रहे) मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से लगा था कि पार्टी में अब शिकायतें सुनी जाने लगेंगी। लेकिन, खड़गे को खुले हाथ से काम नहीं करने दिया गया। ऐसा भी लगता है कि पार्टी के भीतर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दो गुट काम करते हैं, और दोनों के बीच तनाव भी है। पिछले दो साल में बहुत बड़े-बड़े पचास से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें से ज्यादातर भाजपा में गए हैं और वहां महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।

क्यों बनाए जा रहे हैं इतने ज्यादा उप-मुख्यमंत्री

राज कुमार सिंह

संविधान में उप-मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है। फिर भी देश के कई राज्यों में उप-मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पांच उप-मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय, नगालैंड में दो-दो उप-मुख्यमंत्री हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और अरुणाचल में एक-एक उप-मुख्यमंत्री। ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि किसी प्रदेश के बड़े आकार के मद्देनजर जनता को बेहतर शासन देने के मकसद से उप-मुख्यमंत्री का पद गढ़ा जाता है। 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में एक भी उप-मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि मात्र 11 लोकसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में दो उप-मुख्यमंत्री हैं।

राजनीतिक वरिष्ठता और गठबंधन राजनीति के दबावों से बनी जो व्यवस्था कभी अपवादस्वरूप नजर आती थी, वह अब सत्ता के बंदरबांट का फॉर्म्युला बन गई है। एक ही दल को स्पष्ट बहुमत मिलने पर भी उप-मुख्यमंत्री बना कर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधते हुए चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। मुख्यमंत्री एक वर्ग का बनाकर अन्य प्रमुख वर्गों से उप-मुख्यमंत्री बना देने को चुनावी जीत का नया फॉर्म्युला मान लिया गया है।

सवाल है कि क्या किसी खास जाति या समूह का हित उस जाति या समूह का व्यक्ति ही कर सकता है कोई और नहीं? यह भी कि क्या उसके लिए पद नाम उप-मुख्यमंत्री होना भी जरूरी है? हालांकि ऐसी सोच संविधान के तहत ली जाने वाली उस शपथ की भावना के खिलाफ है, जिसमें बिना किसी राग-द्वेष के सबके प्रति समान भाव रखते हुए दायित्व निर्वाह की बात कही जाती है। फिर यह सब चल कैसे रहा है? जाहिर है, सभी राजनीतिक दल सत्ता के ही खिलाड़ी हैं। इसीलिए वैचारिक मतभेदों के दावों के बावजूद उनमें सत्ता के ऐसे खेल पर मौन सहमति है। देश में इस समय जो 26 उप-मुख्यमंत्री हैं, उनमें से सबसे ज्यादा 15 एनडीए के हैं। इनमें भी 13 भाजपा के। राष्ट्रीय राजनीति में हाशिये पर जा चुकी कांग्रेस के तीन उप-मुख्यमंत्री हैं।

राजनीतिक दलों में मौन सहमति के बावजूद कुछ जागरूक संस्थाएं और जनसंगठन ऐसी प्रवृत्तियों को अदालत में चुनौती देते रहते हैं। उप-मुख्यमंत्री पद के विरुद्ध भी देश की सर्वोच्च अदालत में जनहित याचिका दायर की गई, लेकिन परिणाम कुछ खास नहीं निकला- सिवाय इस टिप्पणी के कि संविधान में इस पद का प्रावधान न होने के बावजूद यह प्रवृत्ति असंवैधानिक नहीं है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अतिरिक्त राजनीतिक महत्व देने के लिए भले ही किसी को उप-मुख्यमंत्री कह दिया जाए, पर वास्तव में वह होता मंत्री ही है। वह किसी अतिरिक्त अधिकार या सुविधा का पात्र नहीं होता। बहरहाल, यह कोई नई या हाल में उभरी प्रवृत्ति नहीं है। उप-मुख्यमंत्री ही नहीं, उप-प्रधानमंत्री पद की परंपरा भी भारतीय राजनीति में पुरानी है। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ सरदार वल्लभभाई पटेल उप-प्रधानमंत्री बनाए गए थे। लंबी गुलामी के बाद आजाद हुए और विभिन्न रियासतों में बंटे भारत की चुनौतियां जटिल थीं।

शायद उन स्थितियों का भी तकाजा रहा हो कि प्रधानमंत्री नेहरू के साथ सरदार पटेल के रूप में एक अनुभवी परिपक्व राजनेता मंत्रिमंडल में दूसरे क्रम पर रहे। हालांकि उप-प्रधानमंत्री पद नाम तो निश्चय ही सम्मान के रूप में दिया गया होगा। सरदार पटेल 15 अगस्त, 1947 से 15 दिसंबर, 1950 तक उप-प्रधानमंत्री रहे, पर उसके बाद भी उच्च सत्ता महत्वाकांक्षाओं वाले राजनेताओं में संतुलन की खातिर इस पद नाम का उपयोग किया जाता रहा। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो किसी को उप-प्रधानमंत्री नहीं बनाया, लेकिन भाजपा के ही प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के उत्तरार्ध में 29 जून, 2002 से 22 मई, 2004 तक लालकृष्ण आडवाणी को उप-प्रधानमंत्री बनाया था। भारत में अभी तक सात उप-प्रधानमंत्री रहे हैं। जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा समय भी आया, जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम के रूप में दो-दो उप-प्रधानमंत्री बनाने पड़े। वैसे खुद मोरारजी, 13 मार्च,1967 से 19 जुलाई, 1969 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उप-प्रधानमंत्री रह चुके थे। चौधरी देवीलाल एकमात्र राजनेता रहे, जो चंद महीनों वाली दो सरकारों में उप-प्रधानमंत्री रहे।

पूर्व मुख्यमंत्रियों का दलबदल नई बात नहीं!

अमिताभ श्रीवास्तव

अक्सर राजनीतिक उठापटक के लिए छोटे प्रदेश, कभी बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों के नाम सामने आते हैं। मगर राजनीतिक उठापटक में महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य भी कम नहीं है। यदि अतीत पर नजर दौड़ाई जाए तो राज्य के मराठा छत्रप शरद पवार की राजनीति का पहला और प्रमुख कदम अपनी पार्टी से बगावत और उसके बाद मुख्यमंत्री बनना था। हालांकि इन दिनों महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के बाद से राजनीतिक हलकों में खासी चिंता और चर्चा का वातावरण बन गया है। एक तरफ कांग्रेस में जहां उन्हें पार्टी की पीठ पर छुरा भोंकने वाला से लेकर डरपोक तक कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो राज्य में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों की संख्या सबसे अधिक है। कुछ पार्टी से नाराज होकर गए और कुछ ने रणनीतिक कारणों से अपने दल से विदाई ली।

महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण ने वर्ष 1977 में पूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकते हुए समाजवादी कांग्रेस का गठन किया था। उसके बाद शरद पवार ने वर्ष 1978 में कांग्रेस से विद्रोह करते हुए अपना नया संगठन प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा (पीडीएफ) बनाया था. जिसके बाद वह मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। बाद में उन्होंने वर्ष 1987 में कांग्रेस में वापसी की और दोबारा मुख्यमंत्री बने। एक बार फिर वर्ष 1999 में उन्होंने विद्रोह कर कांग्रेस से अलग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का गठन किया, जो अभी अजीत पवार के विभाजन के बाद दो-फाड़ हुई है। इसी प्रकार शिवसेना के नेता नारायण राणे वर्ष 1999 में भाजपा के साथ तत्कालीन गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वह कांग्रेस में शामिल होकर तत्कालीन कांग्रेस-राकांपा सरकार में मंत्री बने। वर्तमान में वह भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं। इनके अलावा स्वर्गीय विलासराव देशमुख ने कांग्रेस छोड़कर विधान परिषद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार के बाद कांग्रेस में वापसी की और मुख्यमंत्री बने। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर नई पार्टी का गठन कर राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं।

यदि पूर्व मुख्यमंत्रियों के पार्टी छोड़ने के कारणों की समीक्षा की जाए तो उसके पीछे कोई ठोस वजह नजर नहीं आती है। यदि शरद पवार के कांग्रेस छोड़ने के कारण देखे जाएं तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से अधिक नजर कुछ नहीं आता है, क्योंकि पार्टी ने उन्हें काफी कुछ दिया था. यहां तक कि पार्टी छोड़ने के बाद भी उनका महत्व कम नहीं किया। इसी प्रकार शंकरराव चव्हाण ने भी व्यक्तिगत वजह से कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि उस समय भी वह मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। इसी प्रकार नारायण राणे शिवसेना के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भी पार्टी को छोड़ कर चले गए। वहीं विलासराव देशमुख भी पार्टी को छोड़ते समय अच्छी स्थिति में थे। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी हमेशा शिवसेना में अच्छे मंत्रालयों के मंत्री के रूप में काम किया। ताजा मामले में अशोक चव्हाण ने भी हर तरह के मंत्री पद के साथ संगठनात्मक भूमिका में भी काम किया। उन्होंने पार्टी को छोड़ते समय स्वीकार किया कि वह कांग्रेस की आलोचना की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। यदि राज्य का नेतृत्व करने के बाद भी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, कुछ काम करने की इच्छा मन में रह जाती है तो पार्टी छोड़कर मुख्यमंत्री बनने से कुछ आशा की जा सकती है। किंतु किसी दल में सामान्य सदस्य के रूप में शामिल होकर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह निजी लाभ के लिए तो हो सकता है, व्यापक लाभ के लिए नहीं हो सकता।

इसका उदाहरण वर्तमान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के रूप में भी समझा जा सकता है, जिन्हें भाजपा दोबारा राज्यसभा में भेजने के लिए तैयार नहीं है। स्पष्ट है कि किसी दल में दूसरे दल के पूर्व मुख्यमंत्री का शामिल होना खुशी और ताकत दिखाने का मौका हो सकता है। मगर नव आगंतुक की ताकत में वृद्धि की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। प्रचार-प्रसार के दृष्टिकोण से किसी को झटका और किसी को लाभ मिलने का कयास लगाया सकता है। कुछ अपवाद स्वरूप मामले जैसे असम में हेमंत बिस्वा सरमा का आना भाजपा के लिए लाभदायक साबित हो रहा है।

महाराष्ट्र की तुलना में देश के अन्य राज्यों में गुजरात में शंकर सिंह वाघेला, आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु में जयललिता, कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा, ममता बनर्जी जैसे कुछ प्रमुख नेता हैं, जिन्होंने अपने मूल दल से अलग हो कर नया दल गठित किया और मुख्यमंत्री का पद हासिल किया। हालांकि ये सभी नेता नए दलों का गठन करने के लिए जाने गए. इन नेताओं ने न तो मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी दल में प्रवेश किया और न ही पद पाने के बाद अपनी पार्टी छोड़ी थी।

फिलहाल राजनीति के नए दौर में अनेक नेताओं के लिए 'जिधर की हवा, उधर के हम'फार्मूला है। कुछ के लिए यह निष्क्रियता से बाहर निकलने का रास्ता है, कुछ के लिए मजबूरी का कोई सहारा है। यदि नई पारी में परिणाम नहीं मिलते हैं तो राजनीति के नेपथ्य में जाने का भी बड़ा खतरा बना रहता है। हालांकि यह हर नेता की अपनी ताकत, क्षमता और राजनीतिक कुशलता से जुड़ा विषय है। मगर इतना तय है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की निष्ठा बदलना या निष्ठा बदल कर मुख्यमंत्री बनना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के पाला बदलने को लेकर चौंका नहीं जाना चाहिए। न ही उनकी आलोचना की जानी चाहिए। हालांकि चौंकने के अवसर बार-बार नहीं आने के बारे में विचार अवश्य होना चाहिए।

अखिलेश के 'पीडीए' में पीछे छूटते जा रहे हैं पिछड़े-दलित और मुसलमान

संजय सक्सेना

समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर परिवारवाद का आरोप लगता रहता है, लेकिन इससे कभी पार्टी की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सपा में परिवारवाद के बाद अब जिस तरह से बाहरी लोगों को राज्यसभा और विधान परिषद भेजने में दिलेरी दिखाई जा रही है, उससे पार्टी के भीतर बवाल खड़ा हो गया है। वैसे इसकी चिंगारी तभी उठने लगी थी, जब सपा ने लोकसभा के लिये 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। यह चिंगारी सपा प्रमुख द्वारा राज्यसभा के लिये मनमाने तरीके से प्रत्याशियों का चयन करने से और भी भड़क गई है। सपा के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि काम हमारा- अधिकार तुम्हारा नहीं चलेगा। राज्यसभा में जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बाहरी लोगों को टिकट दिया, उससे स्वामी प्रसाद मौर्या ही नहीं कई अन्य नेता भी नाराज हो गये हैं। स्थिति यह है कि सपा का मजबूत वोट बैंक समझे जाने वाला पिछड़ा, दलित, मुसलमान भी अखिलेश के रवैये से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्या पहले ही नाराजगी जता चुके हैं और नई पार्टी के गठन का ऐलान कर चुके हैं जबकि सपा के दलित नेता और पूर्व मंत्री कमलाकांत गौतम ने नाराजगी के चलते अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उधर, मुसलमानों के कई रहनुमा कह रहे हैं कि 90 फीसदी मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं और उनको अधिकार के नाम पर झुनझुना दिखाया जाता है। अखिलेश को बताना होगा कि राज्यसभा के लिये उसे कोई मुस्लिम नेता का नाम क्यों नहीं सूझा। सपा पर अंदर-बाहर सभी तरफ से आरोप लगा रहा है कि उसका पिछड़ा, दलित, मुसलमान (पीडीए) छलावा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर सपा से एक भी मुसलमान नेता को राज्यसभा का टिकट न मिलने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि आपके इस फैसले से सख्त तकलीफ हुई है। मौलाना ने कांग्रेस की तारीफ करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूरे देश में नफरत के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। वह संविधान बचाने, अमन पसंद लोगों को एकजुट करने में जुटे हैं। ऐसे में सपा को साथ देना चाहिए। भाजपा को रोकने के लिए सपा और कांग्रेस को एक मंच पर आना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में फिरकापरस्त ताकतों को मजबूत करने की गलती न करें। मुसलमानों के जज्बात एवं एहसास को ठेस न पहुंचाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सपा की ओर से कांग्रेस को गलत सीटें दी जा रही हैं। इससे स्पष्ट है कि आप लोकसभा में भाजपा के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार उतारने की मंशा रखते हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ जिस उम्मीदवार की घोषणा की गई है, उससे भी यही प्रतीत होता है कि भाजपा को वॉकओवर दे दिया गया है। समाजवादी पार्टी के लिये ऐन चुनाव से पूर्व पार्टी के भीतर उठा बवंडर खतरे की घंटी साबित हो सकता है। समय रहते यदि इसको नहीं थामा गया तो लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि अखिलेश की पीडीए मुहिम को एक के बाद एक झटका लग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद पूर्व मंत्री व सपा के प्रदेश सचिव कमलाकांत गौतम ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। कमलाकांत की बेचैनी भी स्वामी प्रसाद जैसी ही लग रही है। उन्होंने कहा कि सचिव का पद निष्क्रिय व निष्प्रभावी बना दिया गया है। वहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भेदभाव व पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण बहुजन समाज आहत है। पीडीए के ही मुद्दे को लेकर पहले अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने नाराजगी दिखाई थी।

कैंसर का खतराः सिर-गर्दन के कैंसर की जल्द स्क्रीनिंग, रोग के बेहतर उपचार में हो सकती है सहायक

सिर और गर्दन का कैंसर, ट्यूमर का एक समूह है जो मानव शरीर के मुख-गले के क्षेत्रों के आसपास या विभिन्न शारीरिक स्थानों पर विकसित हो सकता है। भारत में सिर और गर्दन का कैंसर एक बड़ा अभिशाप है। चूंकि भारत तम्बाकू और शराब उपभोक्ताओं की एक बड़ी आबादी का घर है इसलिए हमारे देश में सिर और गर्दन के कैंसर की घटना दर बहुत अधिक होना असामान्य नहीं है। भारतीय पुरुषों और महिलाओं दोनों में सिर और गर्दन का कैंसर आमतौर पर नेसल कैविटी, ओरल कैविटी, जीभ, स्वरयंत्र और ग्रसनी में मौजूद स्क्वैमस कोशिकाओं, लार ग्रंथियों या परानासल साइनस की कोशिकाओं में शुरू होता है। यदि कैंसर केवल कोशिकाओं की स्क्वैमस परत तक ही सीमित है, तो इसे कार्सिनोमा इन सीटू कहा जाता है। इसके अलावा इसे इनवेसिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। अफसोस की बात है कि भारत को दुनियाभर में मुंह के कैंसर की राजधानी के रूप में जाना जाता है और इसकी घटनाओं के मामले में यह भारत में शीर्ष तीन कैंसरों में से एक है। भारत में हर साल 2,00,000 से अधिक नए सिर और गर्दन के कैंसर का निदान किया जाता है। भारतीय पुरुषों में लगभग 30% कैंसर सिर और गर्दन के कैंसर और 11-16% भारतीय महिलाओं में होते हैं।

सिर-गर्दन के कैंसर का कारण बनने वाले जोखिम कारक- ये कैंसर मुख्यरूप से तंबाकू, सुपारी, पान चबाने, सिगरेट पीने और अत्यधिक शराब का सेवन करने से होता है। अत्यधिक धूम्रपान करने वाले और धुआं रहित तंबाकू उत्पादों और या शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों में सिर और गर्दन के कैंसर होने का बहुत अधिक खतरा होता है। एपस्टीन बर्र वायरस (ईबीवी) और ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) जैसे वायरस, विशेषरूप से एचपीवी 16 जीनोटाइप, क्रमशः नासॉफिरिन्क्स और टॉन्सिल और जीभ के आधार (ऑरोफरीनक्स) में कैंसर का कारण बनते हैं। खराब पोषण और खराब मौखिक स्वच्छता अन्य जोखिम कारक हैं जो सिर और गर्दन के कैंसर का कारण बन सकते हैं। शोध से पता चलता है कि आनुवांशिकी और पारिवारिक इतिहास भी इनमें से कुछ कैंसर में भूमिका निभाते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले, बार-बार विकिरण के संपर्क में आने वाले और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी) और लैरींगोफैरिंजियल रिफ्लक्स रोग के इतिहास वाले व्यक्तियों में सिर और गर्दन के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

सिर और गर्दन के कैंसर के लक्षण

- गले, गर्दन, कान या मुंह में दर्द होना।
- गर्दन में गांठ।
- मसूड़ों, जीभ, या मुख श्लेष्मा पर लाल या सफेद धब्बे
- मुंह में घाव जो कुछ हफ्तों से ठीक न हुआ हो।
- आवाज में बदलाव, बोलते समय आवाज बैठ जाना।
- चबाने और निगलने में कठिनाई होना।
- नाक या मुंह में रक्तस्राव, दर्द या सुन्नता।
- मुंह खोलने में दिक्कत होना।
- खराब फिटिंग वाले डेन्चर के कारण असुविधा।
- अवरुद्ध साइनस जो एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक नहीं होते।
- चेहरे की मांसपेशियों का पैरालिसिस और ठोड़ी और जबड़े की हड्डी के नीचे सूजन।
- सिर और गर्दन के कैंसर, विशेष रूप से मौखिक गुहा (ओरल कैविटी) के कैंसर से जीवित रहने की दर, कैंसर के चरण या इसके प्रसार की सीमा के आधार पर काफी भिन्न होती है।

निश्चित रूप से, यदि शीघ्र पता चल जाए तो सिर और गर्दन के कैंसर को रोका और ठीक किया जा सकता है। स्क्रीनिंग आमतौर पर दंत चिकित्सकों या ईएनटी डॉक्टरों द्वारा की जाती है। एक व्यवस्थित मौखिक दृश्य परीक्षा आमतौर पर मुंह, गले के क्षेत्र में किसी भी असामान्य घाव और ल्यूकोप्लाकिया, एरिथ्रोप्लाकिया आदि जैसी प्रीमैलिग्नेंट स्थितियों के किसी भी संकेतात्मक लक्षण को देखने के लिए की जाती है।

ल्यूकोप्लाकिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुंह के अंदर एक या अधिक सफेद पैचेस या स्पॉट्स (घाव) बन जाते हैं। दूसरी ओर, एरिथ्रोप्लाकिया, मुंह में श्लेष्म झिल्ली पर असामान्य लाल घावों के रूप में प्रकट होता है। इन पूर्व-घातक स्थितियों के मौखिक कैंसर में विकसित होने की संभावना बहुत अधिक है। चूंकि मौखिक कैंसर अक्सर प्रीमैलिग्नेंट घाव से पहले होता है, इसलिए उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए समय-समय पर जांच कराना सबसे अच्छा होता है जो ल्यूकोप्लाकिया का जल्द पता लगाने में मदद कर सकता है।

प्रारंभिक जांच के बाद, मुंह गुहा और गले की पूरी तरह से शारीरिक जांच की सलाह दी जाती है। गर्दन में लिम्फ नोड्स बढ़ सकते हैं। किसी भी संदिग्ध वृद्धि या घाव के मामले में, टिश्यू बायोप्सी की जाती है। लक्षण विज्ञान (सिम्पटोमोलॉजी) के आधार पर, जांच किए गए रोगी को कैंसर के प्रसार की सीमा निर्धारित करने के लिए सीटी स्कैन, पीईटी स्कैन, एमआरआई, ट्यूमर के बायोमार्कर परीक्षण और एंडोस्कोपी जैसे परीक्षणों के लिए आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है

सिर और गर्दन के कैंसर का उपचार मल्टीमॉडल है, जिसके लिए डॉक्टरों की एक बहु-विषयक टीम (हेड एंड नेक ऑन्को-सर्जन, न्यूरोसर्जन, रिकंसट्रक्टिव सर्जन, डेंटल सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट्स एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट्स, रेडियोलॉजिस्ट्स, पैथोलॉजिस्ट्स और पैलिएटिव केयर फिसिशन्स) की आवश्यकता होती है। इस कारण से, कार्किनोस हेल्थकेयर के डॉक्टरों का पैनल सर्वोत्तम परिणाम के लिए उपचार के सभी आयामों को संबोधित करने के लिए ट्यूमर बोर्ड में एक साथ बैठते हैं।

प्रस्तावित उपचार कैंसर के स्थान, चरण, रोगी की उम्र और उनके समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आमतौर पर प्रारंभिक चरण के कैंसर के लिए सर्जरी की आवश्यकता होगी और स्थानीय रूप से उन्नत बीमारियों के लिए सहायक विकिरण की आवश्यकता होती है। आजकल, विशेष रूप से स्वरयंत्र कैंसर में अंग संरक्षण दृष्टिकोण का अभ्यास किया जाता है।

सिर और गर्दन के कैंसर में, ऑन्कोलॉजिस्ट और अन्य डॉक्टरों की टीम आम तौर पर यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी लेते है कि रोगी का न केवल इलाज किया जाए बल्कि रोगी की उपस्थिति भी बनाए रखी जाए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सर्जरी विकृत हो सकती है, और जीवन की गुणवत्ता भी बनी रहती है।

कार्किनोस हेल्थकेयर जैसी डिजिटल कैंसर देखभाल कंपनियां हर मरीज के लिए एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल तकनीक को तैनात करने पर बहुत जोर दे रही हैं।

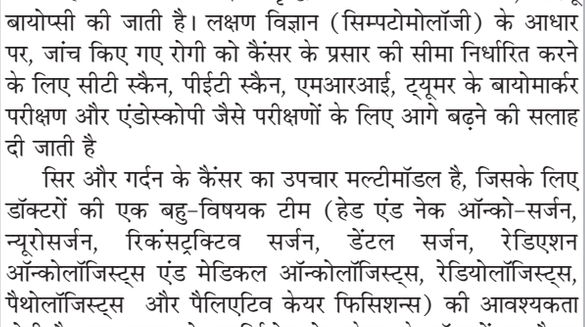

डर्माटोमायोसिटिस

जानिए क्या है वह दुर्लभ बीमारी, जिसने ले ली जूनियर दंगल गर्ल सुहानी की जान

वीकएंड पर हम सभी ने एक दुखद खबर सुनी। आमिर खान की फिल्म दंगल में छोटी बबीता का किरदार अदा करने वाली सुहानी भटनागर का निधन हो गया। अभी वे सिर्फ 19 वर्ष की थीं और अपनी पढ़ाई कर रहीं थीं। शनिवार को दंगल के प्रोड्यूसर और एक्टर आमिर खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर सुहानी के निधन पर दुख प्रकट किया था। असल में सुहानी एक दुर्लभ बीमारी डर्माटोमायोसिटिस से पीड़ित हो गई थीं। जिसका पता बहुत देर से चलता है। जिसके कारण इसका उपचार असंभव हो जाता है। वास्तव में डर्माटोमायोसिटिस एक दुर्लभ बीमारी है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है।

जानिए क्या हुआ सुहानी के साथ

दंगल अभिनेत्री सुहानी भटनागर को 7 फरवरी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। बहुत अधिक कम्प्लीकेशन के कारण 16 फरवरी को डर्माटोमायोसिटिस के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। डर्माटोमायोसिटिस का अब तक सटीक कारण जाना नहीं जा चुका है।

डॉक्टर यह मानते हैं कि मांसपेशियों के वायरल इन्फेक्शन के कारण यह हो सकता है। जब शरीर अपनी मांसपेशियों और शरीर के अन्य ऊतकों में ऑटोएंटीबॉडी विकसित करता है, तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में समस्या होने लगती है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कभी-कभी वैक्सीनेशन, यूवी रेडिएशन यहाँ तक कि पोलूटेंट के कारण भी यह हो सकता है।

क्या हो सकते हैं डर्माटोमायोसिटिस के कारण

19 साल की सुहानी के केस में डॉक्टर मान रहे थे

कि उन्हें दवा के कारण रिएक्शन हुआ होगा, जिसके कारण शरीर में तरल पदार्थ जमा होने की समस्या हो गई। डर्मेटोमायोसिटिस के सटीक कारण का पता लगाना मुश्किल है। मांसपेशियों के वायरल संक्रमण या ऑटो इम्यून डिजीज के अलावा, जिन लोगों में पेट, फेफड़े या शरीर के अन्य हिस्सों में कैंसर है, उनमें यह स्थिति विकसित हो सकती है।

ऑटोइम्यून मायोसिटिस

ऑटोइम्यून मायोसिटिस के लिए वायरस ट्रिगर करने का काम कर सकते हैं। एचआईवी वायरस, जो एड्स का कारण बनता है, वाले लोगों में भी मायोसिटिस विकसित हो सकता है। एचटीएलवी-1 नाम के वायरस वाले लोगों में यह हो सकता है। कभी-कभी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टैटिन जैसी दवाओं के कारण भी हो सकता है। इसमें मरीज का वजन कम होने लगता है। इस रोग की जांच करने पर इसका पता चल पाता है। यह बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, जो प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर 2-3 लोगों को होती है।

किन अंगों को प्रभावित करता है डर्माटोमायोसिटिस

डर्मेटोमायोसिटिस में कंधों, ऊपरी बांहों, हिप्स, जांघों और गर्दन की मांसपेशियां सबसे अधिक कमज़ोर हो जाती हैं। इसमें जोड़ों का दर्द, हृदय और फेफड़ों की मांसपेशियों के ऊतकों में सूजन हो सकता है। साथ ही अन्य अंगों के ब्लड वेसल्स में भी सूजन भी हो सकती है।

कितने समय तक रहता है डर्मेटोमायोसिटिस

डर्माटोमायोसिटिस लगभग पांच वर्षों के बाद रिमिशन या इनएक्टिविटी पीरियड में प्रवेश कर सकता है। अक्सर यह स्थिति क्रोनिक बन जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है। ज्यादातर लोगों को लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए किसी न किसी प्रकार के उपचार की आवश्यकता होती है। जैसे दवा या फिजिकल थेरेपी काम कर सकती है।

क्या यह बीमारी ठीक हो सकती है

डर्मेटोमायोसिटिस दुर्लभ और गंभीर बीमारी है। यह कई मामलों में घातक हो सकती है। जितनी जल्दी हो सके निदान और उपचार शुरू करना जरूरी है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को अक्सर लॉन्ग टर्म -कभी-कभी जीवन भर दवाओं और ट्रीटमेंट से मैनेज किया जा सकता है। उपचार से

जानिए क्या होता है जब आप गैस और एसिडिटी को लगातार इग्नोर करते हैं

अधिकतर लोग अपनी डे टू डे लाइफ में गैस्ट्रिक समस्याओं से होकर गुज़रते हैं। मील स्किप करना, व्यायाम की कमी या ज्यादा तला भुना खाना पेट में एसिड बनाने लगता है, जो अम्लता यानि एसिडिटी का कारण साबित होता है। इससे न केवल मेटाबॉलिज्म वीक होता है बल्कि एपिटाइट पर भी इसका प्रभाव दिखने लगता है। इसके चलते अधिकतर लोगों को जलन, पेट में दर्द और फार्टिंग का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे भी है, जिन्हें थोड़े समय के अंतराल में एसिडिटी से होकर गुज़रना पड़ता है। जानते हैं बार बार बढ़ने वाली एसिडिटी की समस्या के दुष्परिणाम और इससे कैसे करें बचाव।

समझिए क्यों होती है एसिडिटी

एसिडिटी उस मेडिकल कंडीशन को कहा जाता है, जब पेट में अतिरिक्त एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। पेट में मौजूद ग्लैंण्डस उस एसिड को बनाते हैं। बार बार इस एसिड के बनने से पेट में अल्सर, गैस्ट्रिक सूजन, एंग्ज़ाइटी और अपच जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। खाने में अनियमितता, फिज़िकली एक्टीविटी की कमी और स्मोकिंग इस समस्या का मुख्य कारण साबित होते हैं। वे लोग जो ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड खाते हैं, उनमें एसिडिटी का खतरा बना रहता है। आर्टिमिस अस्पताल गुरूग्राम में सीनियर फीज़िशियन डॉ पी वेंकट कृष्णन के अनुसार एसिड रिफ्लक्स उस समस्या को कहते है जब शरीर में लोअर ईसोफैगल स्फिंक्टर यानि मांसपेशियों का एक ग्रुप अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाते है। इससे पेट में एसिड बनने लगता है, जो गले तक पहुंच जाता है। इससे खाना निगलने में भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है।

निगलने में कठिनाई

वे लोग जो एसिडिटी के शिकार होते हैं, उन्हें कुछ भी निगलने में कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। इस मेडिकल कंडीशन को डिस्फैगिया कहा जाता है। एनआईएच के अनुसार पेट में बनने वाले अतिरिक्त एसिड से एसोफेगस यानि फूड पाइप से खाना निगलने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इससे पाचन संबधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं।

सीने में जलन

एनआईएच के अनुसार पेट में बनने वाला अतिरिक्त एसिड जब लीक होकर एसोफेगस में पहुंचने लगता है, तो उस वक्त चेस्ट में जलन की समस्या प्रकट होती है। कुछ मिनटों से लेकर कुछ घण्टों तक इस समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार बिंज ईटिंग भी सीने में जलन का कारण बनती है।

मुंह के स्वाद का बदलना

वे लोग जो बार बार एसिडिटी की समस्या का शिकार होते हैं, उनके मुंह में खट्टास का अनुभव होता है। पेट के बनने वाला ये एसिड गले की ओर बढ़ने लगता है। इससे मुंह में कड़वा या खट्टे स्वाद का अनुभव होने लगता है।

अपच की समस्या

अपच को डिस्पेसीसिया कहा जाता है, जो शरीर में बनने वाली एसिडिटी यानि अम्लता और अन्य पाचन संबधी समस्याओं का कारण बनती है। इसके चलते पेट के अप्पर व मिडल हिस्से में असुविधा व जलन की समस्या बनी रहती है।

किन बातों का रखें ख्याल

हेल्दी फूड्स का करें सेवन- ज्यादा मात्रा में चॉकलेट, कैफीन और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगता है। इससे पेट में दर्द और इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम की समस्या बढ़ने लगती है। ऐसे में आसानी से पचने वाले खाने को खाएं। साथ ही रात को सोने से करीबन 2 घंटे पहले खाना खाएं।

स्मोकिंग है नुकसानदायक- स्मोकिंग शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। इससे एसोफेजियल स्फिंक्टर को नुकसान पहुंचता है, जिससे डाइजेशन स्लो होने लगता है और एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है। नियमित तौर पर अल्कोहल और स्मोकिंग गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है।

व्यायाम करें- फिजिकल एक्टीविटी से शरीर में बनने वाली एसिडिटी से बचा जा सकता है। इससे शरीर हेल्दी और फिट रहता है। साथ ही बोवेल मूवमेंट उचित बना रहता है। दिनभर में कुछ वक्त मॉडरेट एक्सरसाइज़ और योग के लिए निकालें।

तनाव लेने से बचें- छोटी छोटी बातें अगर आपके तनाव का कारण बन रही हैं, तो उसका असर खान पान पर नज़र आने लगता है, जिससे एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है। लंबे वक्त तक कुछ न खाने से शरीर में एसिड को बनाता है, जिससे पेट संबधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

छोटी मील्स लें- एक साथ बहुत कुछ खाने की जगह दिनभर में छोटी मील्स लें। दो घंण्टे के अंतराल में कुछ खाने से बार बार बनने वाली गैस की समस्या हल हो जाती है। साथ ही मोटापे से बचने में भी आसानी होती है।

मुंह का कैंसर : दो दशकों में 50 फीसदी तक बढ़ सकते हैं मामले, पुरुषों में खतरा अधिक

पीबीसीआर के आंकड़ों के अनुसार, ओरल कैविटी पुरुषों में कैंसर का प्रमुख कारण है, जो लगभग 40% कैंसर के लिए जिम्मेदार है, जबकि महिलाओं में यह 6% है। कैंसर के हर तीन में से एक मामला मुंह के कैंसर का हो सकता है। जिले में 48 में से 1 पुरुष को मुंह का कैंसर होने का खतरा है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों (प्रति 100,000 जनसंख्या पर 22.4) में कैंसर की घटना दर 38% अधिक है। इस अंतर को जीवनशैली, खान-पान की आदतों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच के कारण अधिक निदान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

मुंह का कैंसर क्या है?- ओरल कैंसर, मुंह की एक घातक बीमारी है जो जीभ, अंदरूनी गाल, ऊपरी और निचले जबड़े के हिस्से को प्रभावित करती है। यह अधिकतर मौखिक म्यूकोसा के कार्सिनोजेनिक पदार्थों के अत्यधिक संपर्क में आने के कारण बनता है। वाराणसी में इस कैंसर का प्रमुख कारण चबाने वाली तंबाकू (खैनी/सूरती) और सुपारी है। निष्कर्षों से पता चलता है कि जो लोग शराब और तंबाकू दोनों का सेवन करते हैं उनमें मुंह के कैंसर का खतरा उन लोगों की तुलना में 8 गुना अधिक होता है जो दोनों का सेवन नहीं करते हैं। सिगरेट-बीड़ी पीना और सुपारी या पान चबाना भी उतना ही हानिकारक है। कुछ अन्य कारणों में एचपीवी वायरस, खराब फिटिंग वाले डेन्चर शामिल हैं।

चूंकि मुंह के कैंसर के शुरुआती चरण दर्द रहित और लक्षणहीन होते हैं, इसलिए उनका निदान करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सभी संभावित उपचारों को पूरा करने और अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद भी, सफलता (पांच साल तक जीवित रहने) की संभावना कम रहती है। कई कैंसर पीड़ित उच्च स्तर की विकृति और दर्द के कारण मौत का शिकार भी हो जाते हैं। कुछ मरीज जो शुरू में ठीक हो जाते हैं उन्हें बाद की उम्र में कैंसर की पुनरावृत्ति का अनुभव हो सकता है।

मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं?- मुंह के कैंसर आमतौर पर, घाव (शुरुआती लक्षण) सफेद घाव (ल्यूकोप्लाकिया) या लाल घाव (एरिथ्रोप्लाकिया), मुंह में जलन (लाइकेन प्लेनस), मुंह खोलने में परेशानी (ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस) और ठीक न होने वाले अल्सर पैदा कर सकता है। एक बार कैंसर के घातक होने पर मुंह, चेहरे के हिस्से में अनियमित वृद्धि/घाव/ठीक न होने वाले अल्सर को स्पष्ट देखा जा सकता है। ये गर्दन के लिम्फ नोड्स में भी सूजन का भी कारण बन सकती है। मौखिक कैंसर का निदान आमतौर पर परीक्षण (विज़ुअल एग्जामिनेशन)द्वारा किया जाता है, यह मौखिक कैंसर के निदान का एक बहुत ही लागत प्रभावी तरीका है। क्लीनिकल निदान की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर बायोप्सी करते है, जिसमें लोकल एनेस्थीसिया देकर मुंह के प्रभावित क्षेत्र का एक छोटा सा टुकड़ा लेना और माइक्रोस्कोप से इसकी जांच करना शामिल है। यदि कैंसर के निदान की पुष्टि हो जाती है तो रोगी को सीटी स्कैन, एमआरआई या पीईटी स्कैन जैसी आगे की जांच की आवश्यकता हो सकती है।

कैंसर का इलाज- सर्जरी प्रमुख उपचार है जिसके बाद उन्नत मामलों में रेडिएशन और कीमोथेरेपी जैसे सहायक उपचार आते हैं। आदत में सुधार, कैंसर के रोकथाम, शीघ्र निदान की कुंजी है। किसी भी सफेद या लाल धब्बे या दर्द रहित अल्सर के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। इलाज पूरी तरह से निदान के समय पर निर्भर करता है। मुंह के कैंसर का यदि शीघ्र निदान हो जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है।

प्रीटर्म बर्थ का कारण बन सकता है प्रेगनेंसी में खाया गया फास्ट फूड

अगर आप गर्भावस्था से गुज़र रही हैं, तो दवाओं का ख्याल रखने के साथ आहार को ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अपने साथ साथ बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए उचित आहार लेना आवश्यक है। इसमें कोई दोराय नहीं कि महिलाओं को ऐसे समय में खट्टा, कुछ मीठा और तीखा खाने की क्रेविंग होने लगती है। मगर कुछ भोजन ऐसे हैं, जिन्हें खाने से शरीर कई समस्याओं का शिकार हो सकता है। जर्नल एनवायरमेंटल इंटरनेशनल के रिसर्च के अनुसार महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रा.प्रोसेस्ड और फास्ट फूड के सेवन से बचकर रहना चाहिए। इन फूड्स में चीनी और नमक की अधिकता के साथ अनहेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जिसका असर बच्चे की ग्रोथ पर भी पड़ने लगता है। गर्भावस्था के दौरान डाइट में संतुलित और पौष्टिक आहार को बनाए रखना ज़रूरी है। दरअसल, अल्ट्रा.अनप्रोसेस्ड और फास्ट फूड खाने से शरीर को कई प्रकार के नुकसान झेलने पड़ते हैं। जर्नल एनवायरमेंटल इंटरनेशनल की एक स्टडी के अनुसार इन फूड्स में पाया जाने वाला थैलेट केमिकल प्लास्टिक के सामान को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे रैपिंग और पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस केमिकल का मकसद प्लास्टिक के सामान को मज़बूती प्रदान करना है। रिसर्च के अनुसार ये रसायन गर्भावस्था के समय रक्तप्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं और प्लीसेंटा से होता हुआ भ्रूण के रक्तप्रवाह तक पहुंच जाता हैं। रिसर्च के अनुसार गर्भावस्था के दौरान थैलेट इनटेक से फीटस में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन की समस्या बढ़ जाती है। रिसर्च के अनुसार इसके चलते बच्चे में लो बर्थ वेट, प्रीटर्म बर्थ, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे ऑटिज़्म और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की शिकायत हो सकती है। इससे मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव दिखने लगता है। ऐसे में इस प्रकार के फूड्स का सेवन करने से बचें। इस बारे में हेल्थ शॉटस की टीम से बातचीत करते हुए नूट्रिशनिस्ट और हॉलिस्टिक वेलनेस कोच इशांका वाही ने कई बातों की जानकारी दी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

यात्रा से ब्रेक लेकर कैम्ब्रिज विवि में लेक्चर देंगे राहुल

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' से कुछ दिनों का विराम लेकर इस महीने के आखिर में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में व्याख्यान देंगे और फिर पार्टी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को यह जानकारी दी। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 39वां दिन बुधवार को दोपहर दो बजे कानपुर में समाप्त हुआ। 22 और 23 फ़रवरी को यात्रा में विराम होगा। उन्होंने कहा कि 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' 24 फ़रवरी की सुबह मुरादाबाद से फ़िर शुरू होगी। उसके बाद संभल, अलीगढ़, हाथरस, और आगरा ज़िलों से गुजरते हुए यात्रा राजस्थान के धौलपुर में रुकेगी। रमेश ने कहा, 26 फ़रवरी से एक मार्च तक विराम होगा ताकि राहुल गांधी 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (जहां से वह पढ़े हैं) में दो विशेष व्याख्यान देने के अपने एक साल पहले के वादे को पूरा कर सकें।

मोदी संसद के दरवाजे पर झुकते हैं, वह नाटक है : पवार

मुंबई। वरिष्ठ राजनेता शरद पवार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में केवल 20 मिनट के लिए आते हैं जब संसद में आम लोगों के मुद्दों पर चर्चा होती है और नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने संसद के दरवाजे पर झुकने के पीएम मोदी के इशारे को नाटकीयता भी कहा। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि सत्र की शुरुआत में (प्रधानमंत्री) संसद के दरवाजे पर झुकते हैं। यह नाटक है। कोल्हापुर में मारे गए वामपंथी नेता गोविंद पानसरे के स्मारक का अनावरण करने के लिए आयोजित एक समारोह में बोलते हुए, पवार ने कहा कि प्रतिगामी शक्तियों के खिलाफ एकजुट रुख होना चाहिए। शरद पवार ने आरोप लगाया कि आज सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, स्वतंत्र आवाज़ को दबाया जा रहा है, स्वतंत्र लेखन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और समाचार चैनलों को अवरुद्ध किया जा रहा है। इसका मतलब है कि सत्ता में बैठे लोगों को मौलिक अधिकारों पर हमलों की कोई परवाह नहीं है।

जिशान सिद्दीकी को मुंबई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने के कुछ दिनों बाद, सबसे पुरानी पार्टी ने उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें मुंबई युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया। इस महीने की शुरुआत में बाबा सिद्दीकी अजित पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की घोषणा की और पार्टी से अपना 48 साल पुराना नाता तोड़ दिया। जीशान को हटाकर अखिलेश यादव को मुंबई यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि वह आगे बढ़ गए हैं क्योंकि अब इस पुरानी पार्टी में उनकी जरूरत नहीं थी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी वर्तमान में मुंबई के बांद्रा (पूर्व) से कांग्रेस विधायक हैं। सिद्दीकी 1999, 2004 और 2009 में लगातार तीन बार विधायक रहे।

संदेशखाली मामले को लेकर भाजपा का ममता पर वार

नईदिल्ली। संदेशखाली मामले को लेकर भाजपा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। इसी मामले पर बोलते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संदेशखाली मामला गंभीर है। महिलाओं पर खुलेआम हमले, अपमानजनक व्यवहार और यौन उत्पीड़न के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं, वह हमारे समाज और लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब भी इसका बचाव कर रही हैं। क्यों?...एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया। ममता बनर्जी क्या छिपाना चाहती हैं और क्यों? एक महिला सीएम अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए महिलाओं के सम्मान को खतरे में डाल रही हैं। क्यों? उसका ज़मीर कहां मर गया?... पार्टियां चुप क्यों हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैंने सुना है कि सीपीआई (एम) की एक महिला नेता ने क्षेत्र का दौरा किया लेकिन सीपीआई (एम) ने इसका (घटना) विरोध नहीं किया है।

शीर्ष अदालत का पश्चिम बंगाल सरकार को झटका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर मुकदमे को तत्काल सूचीबद्ध करने पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। बता दें, राज्य सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पर कानून के तहत राज्य से आवश्यक मंजूरी हासिल किए बिना चुनाव बाद हिंसा के मामलों में अपनी जांच आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि मामले की सुनवाई नौ बार स्थगित की जा चुकी है। साथ ही बताया कि यह मामला न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। उन्होंने कहा, मामला सामने आ रहा है, लेकिन हम संविधान पीठ के समक्ष हैं। अगर इस पर बुधवार या गुरुवार को सुनवाई हो सकती है। इस पर किसी तरह का आदेश देने से इनकार करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मैं मामले पर सुनवाई नहीं कर रहा हूं। आप उस बेंच के समक्ष जाइए, वे ही फैसला लेंगे।

लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को साधेंगे राजनाथ सिंह, भाजपा ने बनाई अचूक रणनीति

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 मार्च को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक महा किसान रैली को संबोधित करने वाले हैं। रैली का उद्देश्य किसानों से जुड़ना है, और 1 लाख से अधिक किसानों के भाग लेने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम किसानों को मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई लाभकारी योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में काम करेगा। इसके अतिरिक्त, किसानों को सुझाव देने और अपनी चिंताएं व्यक्त करने का अवसर मिलेगा।

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने रैली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जोर दिया कि यह किसानों की समस्याओं को समझने और उनके सुझाव एकत्र करने पर केंद्रित होगी। किसानों को सरकार के विचार में योगदान देने के लिए अपने सुझाव या समस्याएं लिखने के लिए मतपेटियां उपलब्ध होंगी। चाहर ने पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना समेत किसानों के लिए मोदी सरकार की पहल की सराहना की। रैली में इन योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल होगा। इस आयोजन में राज्य के मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के भी भाग लेने की उम्मीद है।

हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों ने कुछ युवा किसानों द्वारा बुधवार को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर कई चरणों वाले अवरोधकों की ओर बढ़ने के बाद आंसू गैस के गोले छोड़े। हरियाणा पुलिस ने सुबह करीब 11 बजे आंसू गैस के गोले छोड़े जिसके बाद युवा किसान बचने के लिए इधर-उधर भागते दिखे। पंजाब और हरियाणा के बीच दो सीमा बिंदुओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान बुधवार को अपना ''दिल्ली चलो'' मार्च फिर से शुरू कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा पांच साल तक दालें, मक्का और कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद वे अपना आंदोलन फिर से शुरू कर रहे हैं।

सरकार ने किसान संगठनों को फिर दिया बातचीत का न्योता

केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक

एमएसपी समेत कई अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसानों को पांचवें दौर की बातचीत का न्योता दिया है। उन्होंने चौथे दौर में दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत का भी ब्योरा दिया।

मुंडा ने कहा, चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों की ओर से जो प्रतिक्रिया आई उसे संज्ञान में लेते हुए हम पांचवे दौर की बैठक और स्स्क की मांग, फसल विविधीकरण, पराली का विषय जैसे मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मेरी अपील है कि वे शांति बनाएं रखें और हमारी कोशिश है कि वार्ता से समाधान निकले।

गौरतलब है कि किसानों के 21 फरवरी से फिर दिल्ली कूच के एलान पर अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि किसान नेताओं ने एमएसपी पर सरकार के प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया है। मैं किसानों और किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। साथ ही उन्होंने मुद्दों के समाधान के लिए चर्चा करने की बात की। उन्होंने किसानों से अपील में कहा था कि हमें मुद्दे पर चर्चा करते रहना चाहिए, हम सभी शांति चाहते हैं और हम सबको मिलकर समस्या का समाधान निकालना है।

सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का हक : खड़गे

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर प्रदर्शनकारी किसानों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि केंद्र को किसानों की उचित मांगों को पूरा करना चाहिए और आवश्यक फसलों पर एमएसपी प्रदान करना चाहिए। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में एमएसपी पर कानूनी गारंटी भी शामिल करेगी।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम उनका (किसानों) समर्थन कर रहे हैं। हम खुले तौर पर कह रहे हैं कि उनकी उचित मांगें पूरी होनी चाहिए।% हम अपने चुनावी घोषणापत्र में भी यह कहने जा रहे हैं कि कानूनी गारंटी दी जायेगी। सभी फसलों को कवर नहीं किया जा सकता लेकिन आवश्यक फसलों को कवर किया जाना चाहिए। इससे पहले, पार्टी नेता राहुल गांधी ने एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं करने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा था कि जिस देश में 14 लाख करोड़ के बैंक ऋ्ण माफ कर दिए गए हैं, 1.8 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई है, वहां किसानों पर थोड़ा सा खर्च भी क्यों नज़रअंदाज़ किया जाता है? एमएसपी की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में मांग बढ़ेगी और किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने का आत्मविश्वास भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है। जो लोग एमएसपी पर भ्रम फैला रहे हैं वे डॉ. स्वामीनाथन और उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी से भारतीय किसान बजट पर बोझ नहीं बल्कि जीडीपी ग्रोथ के संचालक बनेंगे।

पटना में 3 मार्च को होगी महागठबंधन की रैली

राहुल गांधी भी होंगे शामिल

नईदिल्ली। लोकसभा चुनाव के दहलीज पर देश खड़ा है। यही कारण है कि राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच बिहार में कांग्रेस और राजद की एक बड़ी रैली होने वाली है। इस रैली में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि महागठबंधन ने 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा आयोजित करने का फैसला किया है। रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के लालू यादव और तेजस्वी यादव शामिल होंगे।

वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपनी 10 दिवसीय जन विश्वास यात्रा शुरू करते हुए अपनी पार्टी के लिए एक नया, समावेशी नारा दिया, जिसके दौरान वह बिहार के 38 जिलों की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि राजद मेरी पार्टी है। राजद अकेली मेरी (मुस्लिम-यादव) पार्टी नहीं है। इसका आधार बहुत बड़ा है और यह ए से जेड तक के लोगों का है। हमें उन्हें बताना है कि हमारी पार्टी राजद केवल (एमवाय) पार्टी नहीं बल्कि बीएएपी पार्टी भी है। उन्होंने कहा कि हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं। बीजेपी लोगों को बांटना चाहती है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ''भारत जोड़ो न्याय यात्रा'' शुक्रवार को बिहार के सासाराम जिले से फिर से शुरू हुई और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव इस यात्रा में शामिल होने के साथ कांग्रेस नेता के सारथी की भूमिका में दिखाई दिए। कांग्रेस सांसद राहुल ने रोहतास जिले के डेहरी मुफस्सिल थाना अंतर्गत जमुहार में रात्रि विश्राम के बाद तेजस्वी के साथ एक लाल खुली जीप में सवार होकर यात्रा कीशुरुआत की। तेजस्वी जीप चला रहे थे वहीं कांग्रेस नेता राहुल बगल की सीट में बैठे थे। जीप में पीछे लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार बैठी हुई थीं। दोनों युवा नेताओं ने सड़क पर एकत्र

भीड़ की ओर हाथ हिला कर उनका अभिवादन किया।

उत्तरप्रदेश में सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव

लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार शाम को दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक स्थानीय होटल में शीट शेयरिंग के फैसले की जानकारी दी। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय ने बताया कि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को यूपी में सपा के साथ समझौते में 17 सीटें मिली हैं। इनमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, बनारस, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, हाथरस, बाराबंकी, देवरिया शामिल है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस हाई कमान के बीच बुधवार सुबह से ही सीटों को लेकर एक बार फिर बातचीत हुई है। प्रेस कांफ्रेंस में सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद हैं। गौरतलब है कि दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बना गतिरोध कल रात तक जारी रहा। जिसके कारण सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव घोषणा करने के बावजूद रायबरेली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए।

खेल
प्रमुख समाचार

भारतीय टीम को झटका, चौथे टेस्ट से बुमराह और राहुल बाहर

नईदिल्ली। भारतीय टीम को रांची टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है। कप्तान रोहित शर्मा के साथ कठिन चुनौती है। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। सीरीज का चौथा मैच रांची में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने कहा कि तेज गेंदबाज और टीम इंडिया के उप कप्तान जसप्रीत बुमराह और मध्यक्रम के बल्लेबाज केएल राहुल टेस्ट नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार से रांची में होने वाले चौथे टेस्ट के लिए भारत तेज गेंदबाज बुमराह के बिना होगा। बीसीसीआई ने यह भी कहा कि मध्यक्रम के बल्लेबाज केएल राहुल सीरीज के पहले टेस्ट में लगी चोट के कारण अनुपलब्ध रहेंगे। राजकोट में तीसरे टेस्ट के लिए टीम से रिलीज किए गए मुकेश कुमार रांची में टीम में शामिल हो गए हैं। सीरीज में 17 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बुमराह की अंतिम टेस्ट के लिए टीम में वापसी की संभावना है। हैदराबाद में शुरुआती मैच में हार के बाद वापसी करते हुए भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ रांची में होने वाले चौथे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेस्ट के लिए टीम से रिलीज कर दिया गया है। मौजूदा श्रृंखला की अवधि और हाल के दिनों में उनके द्वारा खेली गई क्रिकेट मैचों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।'' उन्होंने कहा, ''इस बीच लोकेश राहुल चौथे टेस्ट से भी बाहर रहेंगे। धर्मशाला में अंतिम टेस्ट मैच में उनकी भागीदारी फिटनेस पर निर्भर है।

भारतीय टीम- रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, देवदत्त पडिक्कल, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), केएस भरत (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, आकाश दीप।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 434 तो निफ्टी 142 अंक फिसला

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में पिछले छह ट्रेडिंग सेशन से जारी तेजी पर बुधवार को ब्रेक लग गई जिससे स्टॉक मार्केट गिरकर बंद हुई। अमेरिकी की ब्याज दरों में जल्द कोई कटौती की उम्मीद कम होने के कारण ढ्ढ्ढ शेयरों और एनर्जी स्टॉक्स में गिरावट के चलते बाजार गिरकर बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज पिछले बंद भाव 73,057.40 के मुकाबले उछलकर 73,267.48 पर खुला और कारोबार के दौरान एक इससे ऊपर नहीं गया। अंत में सेंसेक्स 0.59 प्रतिशत या 434.31 अंक की गिरावट लेकर 72,623.09 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ़्टी-50 भी 0.64 प्रतिशत या 141.90 अंक की गिरावट के साथ 22,055.05 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील 1.99 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ। साथ ही स्टेट बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक समेत 10 कंपनियों के शेयर ग्रीन कलर में बंद हुए।

बायजूज का राइट्स इश्यू पूरा हुआ सब्सक्राइब

नईदिल्ली। परेशानियों से घिरी एडटेक कंपनी बायजूज के लिए राहत की खबर है। कंपनी का 1,650 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। इस बारे में कंपनी के फाउंडर और सीईओ बायजू रवींद्रन ने शेयरहोल्डरों को भेजे एक लेटर में जानकारी दी। बता दें, कंपनी ने यह राइट इश्यू अपने पीक वैल्यूएशन से करीब 99 फीसदी कम भाव पर जारी किया था। इस बारे में सूत्रों की जानकारी के अनुसार, फाउंडर इस राइट इश्यू में करीब 375 करोड़ रुपये तक निवश करने की तैयारी में है, जिसमें वह कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखे। बता दें, इसी हफ्ते के आखिर में कंपनी के शेयरधारकों की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होनी है। इस मीटिंग को बायजू के कुछ सबसे बड़े निवेशकों ने कंपनी के नेतृत्व को हटाने और इसके बोर्ड को रिस्ट्रक्चर करने के लिए 23 फरवरी को बुलाया है।

अमेरिका से भारत में सेब का निर्यात 16 गुना बढ़ा

नईदिल्ली। अमेरिका से भारत में सेब का निर्यात पिछले साल की तुलना में 16 गुना बढ़ा है। भारत के अमेरिकी उत्पादों पर 2019 में लगाए गए 20 प्रतिशत प्रतिशोधात्मक शुल्क को हटाने का फैसला करने के बाद यह निर्यात बढ़ा है। वाशिंगटन राज्य के सेब उत्पादकों ने इस वर्ष करीब 10 लाख पेटी सेब भारत भेजे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 गुना अधिक है। सिएटल बंदरगाह पर मंगलवार को इस उपलब्धि का जश्न मनाया गया। सांसद मारिया केंटवेल ने सिएटल में पत्रकारों से कहा, '' यह अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंधों में एक नया मुकाम है।'' इस खास अवसर का सिएटल में भारत वाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता, मध्य वाशिंगटन के सेब उत्पादक और श्रम व बंदरगाह अधिकारी भी साक्षी बने। सेब पर आयात शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि के कारण वाशिंगटन राज्य से भारत तक सेब निर्यात बाजार में गिरावट आई थी।

जी ने 2000 करोड़ के हेर-फेर की रिपोर्ट का खंडन किया

नईदिल्ली। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बुधवार को उस रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने पाया है कि कंपनी ने अपने अकाउंट्स से लगभग 2,000 करोड़ रुपये के फंड का 'डाइवर्जन' किया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कहा, जी में अकॉउंटिंग मुद्दों से संबंधित रिपोर्ट और अफवाहें 'गलत और झूठी' हैं। हम सेबी द्वारा अनुरोधित सभी टिप्पणियाँ प्रदान करने की प्रक्रिया में हैं और हमने सभी पहलुओं पर पूरा सहयोग दिया है। रेगुलेटर सेबी ने अपनी जांच में खुलासा किया है कि कंपनी में करीब 240 मिलियन डॉलर (करीब 2000 करोड़) के फंड डायवर्जन हुआ है। बता दें, न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी सामने आई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर सवाल उठाने वाले जरा तथ्यों पर गौर करें

प्रह्लाद सबनानी

भारत में पिछले एक दशक में, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में, अतुलनीय सुधार दृष्टिगोचर है और भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बन गई है। आगे आने वाले लगभग पांच वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ऐसा आकलन विश्व के कई वित्तीय एवं आर्थिक संस्थान कर रहे हैं। आज विश्व के कई देश पूंजीवादी मॉडल से निराश होकर भारतीय आर्थिक मॉडल को अपनाने की बात करने लगे हैं क्योंकि सनातन संस्कृति पर आधारित भारतीय आर्थिक मॉडल पश्चिमी आर्थिक मॉडल की तुलना में बेहतर माना जा रहा है। परंतु, दुर्भाग्य से भारत में कुछ राजनैतिक दल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए भारत में हाल ही के समय में हुई आर्थिक प्रगति को कमतर आंकते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलाव की ब्यार पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते दिखाई दे रहे हैं।

भारत आज अर्थ के विभिन्न क्षेत्रों में नित नई ऊंचाईयां छू रहा है। दिसम्बर 2023 के प्रथम सप्ताह में भारत ने फ्रान्स एवं ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए शेयर बाजार के पूंजीकरण के मामले में पूरे विश्व में पांचवां स्थान हासिल किया था। भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन, जापान एवं हांगकांग थे। परंतु, अब दो माह से भी कम समय में भारत ने शेयर बाजार के पूंजीकरण के मामले में हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। अब ऐसा आभास होने लगा है कि भारत अर्थ के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर खोई हुई अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करता

हुआ दिखाई दे रहा है। एक ईसवीं से लेकर 1750 ईसवीं तक आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का बोलबाला था। इस खंडकाल में विश्व के कुल विदेशी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से भी अधिक की रही है क्योंकि उस समय पर भारत में सनातन संस्कृति का पालन करते हुए व्यापार किया जाता था। भारत में कर्म एवं अर्थ के कार्यों को धर्म का पालन करते हुए करने की प्रथा का पुरातन शास्त्रों में वर्णन मिलता है। भारत में चूंकि आज एक बार पुनः सनातन संस्कृति का पालन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य सम्पन्न हो रहे हैं अतः पूरे विश्व का भारत पर विश्वास बढ़ रहा है। विदेशी निवेश के साथ साथ आज लगभग 50 देश भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करना चाहते हैं क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर विभिन्न उत्पादों के लिए एक बहुत बड़े बाजार के रूप में विकसित हो रहा है।

ऐसा कहा जाता है कि शेयर बाजार में निवेशक अपनी जमापूंजी का निवेश बहुत सोच विचार कर करता है एवं जब निवेशकों को यह आभास होने लगता है कि अमुक कम्पनी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है एवं निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल अधिकतम रहने की सम्भावना है, तभी निवेशक अपनी जमापूंजी को शेयर बाजार में उस अमुक कम्पनी में निवेश करते है। इस प्रकार, जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का भरोसा बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो विशेष रूप से विदेशी निवेशक एवं विदेशी संस्थागत निवेशक उस देश में विभिन्न कम्पनियों के शेयर में अपनी निवेश बढ़ाते हैं। चूंकि विदेशी संस्थानों को आगे आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एवं भारतीय कम्पनियों की विकास यात्रा पर भरपूर भरोसा है अतः भारतीय शेयर बाजार में निवेश भी रफ्तार पकड़ रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज भारत एक वैश्विक ताकत बनाकर उभरा है। भारत आज न केवल अपने लिए सेटेलाईट अंतरिक्ष में भेज रहा है बल्कि विश्व के कई अन्य देशों के लिए भी सेटेलाईट अंतरिक्ष में स्थापित करने में सक्षम हो गया है। किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति तभी सफल मानी जानी चाहिए जब उस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक को भी उस देश की आर्थिक प्रगति का लाभ मिलता दिखाई दे। इस दृष्टि से विशेष रूप से गरीबी एवं आय की असमानता को कम करने में भारत ने विशेष सफलता पाई है।

जन्मदिन पर मुख्यमंत्री साय का न्योता भोज, अपनी थाली की मिठाई बाजू में बैठे बच्चों को दे दी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्मदिन पर मौके पर हर कोई अपने लाडले मुख्यमंत्री को बधाई दे रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने भी अपने अंदाज में मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अपने मन में बच्चों के प्रति कितना स्नेह रखते हैं। यह उनके जन्मदिन के अवसर पर बगिया के आश्रम शाला में आयोजित न्योता भोज के दौरान छोटे-छोटे प्रसंगों में सामने आया। मुख्यमंत्री और बच्चों को जब भोजन परोसा गया तो मुख्यमंत्री ने अपनी थाली की मिठाई अपने बगल में बैठे बच्चों अनुज और सुमीत को दे दी। खाने के दौरान मुख्यमंत्री उनसे ढेर सारी बातें करते रहे। बच्चों को मुख्यमंत्री घर के मुखिया की तरह लगे। बच्चों को मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी को खूब मन लगाकर पढ़ना है। ऊंचे मुकाम पर आपको पहुंचना है। नन्हे बच्चे भी मुख्यमंत्री श्री साय को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित रहे और मुख्यमंत्री से कहा कि सीएम सर हमसे मिलने और आइएगा। मुख्यमंत्री साय बच्चों की इस मासूम मनुहार पर मुस्कुराए और कहा बगिया तो मेरा घर है तो आप लोगों से मिलने तो आता ही रहूंगा। बगिया के बालक आश्रम के नन्हें बच्चों का दिन आज बेहद खास रहा क्योंकि उनके बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वो भी अपना जन्मदिन मनाने। बच्चों ने मुख्यमंत्री श्री साय को कविता के माध्यम से जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। उन्होंने बच्चों को केक खिलाया और उन्हें क्रिकेट किट, बैडमिंटन, वॉलीबाल जैसी खेल सामग्री उपहार में दिए। इस मौके पर पद्मश्री जागेश्वर यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परंपरा की शुरुआत की है जिसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना को सामुदायिक सहयोग से और अधिक पोषक बनाने की पहल की गई है। इसी के तहत आज अपने जन्मदिन मनाने बगिया बालक आश्रम शाला के बच्चों के बीच पहुंचा हूँ और न्योता भोज में आपके साथ बैठकर भोजन का आनंद लिया। उन्होंने दूसरों से भी अपील करते हुए कहा कि किसी जन्मदिन, वर्षगांठ जैसे खास मौकों पर अपने पास के स्कूल, आश्रम, छात्रावास में जाकर बच्चों के साथ न्योता भोज में जरूर शामिल हों। इससे समुदाय में अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि और सभी समुदाय वर्ग के बच्चों के बीच समानता की भावना विकसित करने के लक्ष्य की पूर्ति होगी।

इस दौरान आईजी श्री अंकित गर्ग, सीसीएफ नवीद सजाउद्दीन, कलेक्टर डॉ रवि मित्तल, एसपी शशि मोहन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

त्यागी जीवन के अद्भुत मिसाल!

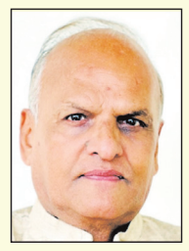

जैन समाज ही नहीं, भारतीय समाज ही नहीं, पूरे विश्व समाज की एक बड़ी क्षति है आचार्य श्री विद्यासागर जी का महाप्रयाण। कर्नाटक में जन्मे इस महान संत ने अपने जीवन कर्म से दक्षिण और उत्तर को समरस कर दिया था सात आठ भाषाओं के वे ज्ञाता थे। दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने राजस्थानी और हिंदी सीखी। इनसे कभी मिलने का सौभाग्य नहीं मिला लेकिन उनके बारे में निरंतर पढ़ता, सुनता रहा। गौ माता के संरक्षण हेतु किए गए उनके प्रयासों को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इनके आशीर्वाद से ही अनेक जगह गौशालाएं चल रही हैं। इनके निधन को हमारे एक प्रसिद्ध हमारे मित्र डॉक्टर यतीश जैन ने कहा, 'यह केवल शोक का विषय नही भारत के इतिहास में आचार्य श्री विद्यासागर जी का 'जयवंत दिवस' है ।1966 से चल रही आध्यात्मिक यात्रा का विराम 18 फरवरी माघ शुक्ल नवमी के दिन हुआ।' आचार्य विद्यासागर जी ने अपने एक वीडियो में सबको यह संदेश दिया था कि एक दिन तो इस संसार से सबको जाना ही है इसलिए रोना-धोना नहीं। यतीश जी के माध्यम से मुझे जब आचार्य श्री के बारे में जानकारी मिली तो मैं दंग रह गया। वे सचमुच वीतरागी थे। तपस्वी थे। त्यागी संत थे। उनका अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं था। वे तो दिगंबर थे इसलिए उनकी कोई जेब भी नहीं थी जिसमें वे कुछ पैसे रखते। लेकिन उनको मानने वाले लोगों के पास अकूत दौलत थी। इसलिए आचार्य श्री का आदेश मानकर लोग खुलकर दान किया करते थे। उनका पूरा जीवन अद्भुत त्याग का मिसाल है। हम उनके संकल्पों को देखें तो चकित रह जाएंगे। मेरे जैसा व्यक्ति तो कभी किसी नियम का पालन ही नहीं कर सकेगा। उन्होंने आजीवन चीनी, नमक, दही,हरी सब्जी, सूखे मेवे, तेल, फल का त्याग किया। कठिन साधना यह कि उन्होंने थूक भी त्याग दी थी। चटाई पर सोते थे। कोई गद्दा नहीं, कोई तकिया नहीं। ठंड में भी बिना किसी वस्त्र के रात निकाल देने वाले तपस्वी। अंग्रेजी दवाई कभी नहीं खाई। हाथ में भोजन आ गया, उसे ही ग्रहण किया। अंजुरी में जितना जल आ गया, उसी को पीकर तृप्ति कर ली। और यह क्रम वर्षों से निरंतर जारी रहा। उनकी काया जर्जर हो चुकी थी लेकिन मन जीवंत बना रहा । वे प्रवास करते और लोगों को बेहतर जीवन जीने का संदेश देते रहते। अंतिम समय में वे डोंगरगढ़ में बने भव्य चंदगिरि मंदिर परिसर में रहते हुए समाज का मार्गदर्शन कर रहे थे। उनके गौरवशाली इतिहास को जब हम देखते हैं, तो पाते हैं कि यह किशोरावस्था से ही ब्रह्मचारी व्रत धारण करके संन्यासी होना चाहते थे। जब घर वालों ने मना किया तो आपने तीन दिन तक लगातार निर्जला उपवास किया। आखिरकार सबको अपनी जिद छोड़नी पड़ी और आचार्य विद्यासागर संत बन गए। गौशालाओं के निर्माण में उनकी अद्भुत भूमिका रही। इसका जिक्र मैंने अपने उपन्यास %एक गाय की आत्मकथा% में भी किया है। आपने न केवल देसी गायों की चिंता की वरन बालिका शिक्षा की दिशा में भी काफी कार्य किया। वे दिगंबर संत थे। सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन वह सबसे यही अपेक्षा करते थे कि राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करते रहें। उन्हें अपने महाप्रयाण के बारे में पता चल गया था। इसलिए उन्होंने तीन दिन पहले से ही कुछ भी ग्रहण करना बंद कर दिया था । उन्होंने आचार्य पद का भी त्याग करके अपने उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य समय सागर को नामांकित कर दिया था। उनके अंतिम दर्शन करने जो हजारों लोग डोंगरगढ़ पहुँचे, वे सब उनकी कृशकाय छवि को देखकर जरूर द्रवित हुए लेकिन आचार्य जी के चेहरे पर जो तपस्वी भाव था, वह उनकी महानता की गाथा कह रहा था। कर्नाटक में जन्मे और छत्तीसगढ़ में जीवन से मुक्त हुए। यह इस राज्य का भी परम सौभाग्य कहा जा सकता है।

राजस्व मंत्री वर्मा के विभागों के लिए 3608 करोड़ रूपए से अधिक की अनुदान मांगे पारित

दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान

- सकर्रा और चकरभाठा को उप तहसील बनाने की घोषणा
- नगरीय क्षेत्रों के ग्रामों में चांदा-मुनारा की पुर्नस्थापना के लिए 16 करोड़ रूपए

रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए 3608 करोड़ 47 लाख 81 हज़ार रुपए की अनुदान मांगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सर्वसम्मति से पारित की गई। इनमें भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए 2072 करोड़ 16 लाख 69 हजार रुपए, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए 30 करोड़ 23 लाख 22 हज़ार रुपए, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए 1433 करोड़ 38 लाख 73 हज़ार रुपए और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 72 करोड़ 69 लाख 17 हज़ार रुपए शामिल है।

अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की मांगों से विभागीय मंत्री को अवगत कराया और सुझाव भी दिए। अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने मुंगेली जिले के चकरभाठा और बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के सकर्रा में उप तहसील कार्यालय खोलने की घोषणा की। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि राजस्व विभाग भूमि संबंधी अभिलेखों का संधारण करता है, वहीं शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उसे आम जनता तक पहुंचाने का काम राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने विभागीय नियमों व प्रक्रियों में लगातार सुधार एवं उन्नयन करते हुए नवीन तकनीक का उपयोग कर रही है। इसके लिए बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं।

वर्मा ने सदन में कहा कि ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं के लिए अभिलेखों के दुरुस्तीकरण, हस्ताक्षरयुक्त खसरा एवं बी-1 डिजिटल कापी, ई-कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार गरीबों और मजदूरों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत पंजीकृत किसानों को 10 हजार रूपए वार्षिक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटवारी नक्शों के जियोरिफ्रेसिंग कार्य के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों के ग्रामों में चांदा-मुनारा के लिए 16 करोड़ रूपए, प्रदेश के सभी तहसील कार्यालयों में कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि के लिए 115 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। नवगठित अनुविभागों एवं तहसीलों के कार्यालय भवन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय की नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पीड़ितों के हितों की भी चिंता की है। वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य आपदा मोचननिधि के लिए 533 करोड़ 60 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए 50 करोड़ रुपए, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए 133 करोड़ 40 लाख रूपए, निर्देशन व प्रशासन के लिए 3.26 करोड़ रूपए तथा आपदाओं का विश्लेषण एवं योजना तैयार करने के लिए 58 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री वर्मा ने विभागीय अनुदान मांगों की चर्चा के उत्तर में कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में हमारी सरकार युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।

इसके लिए 20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना हेतु एक करोड़ 50 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 10 करोड़ 65 लाख से अधिक की राशि प्रावधानित है। राज्य युवा महोत्सव के लिए 4 करोड़ रूपए, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के लिए एक करोड़ 40 लाख रूपए, महिला खेलकूद प्रतियोगिता के लिए एक करोड़ रूपए, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए एक करोड़ रूपए, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के लिए एक करोड़ रूपए, युवा कल्याण गतिविधियों के लिए 3 करोड़ रूपए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए 2 करोड़ 85 लाख रूपए, राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के लिए 5 करोड़ रूपए, खेल संघों एवं संस्थाओं को अनुदान के लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री साय को जन्मदिन की बधाई दी

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, छत्तीसगढ़ के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में शाह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन की सरकार छग में गरीब कल्याण और सुशासन के नए कीर्तिमान बनाएगी।

अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने साय के सदैव स्वस्थ,सुखी और दीर्घायु रहने की कामना की है।

उप्र के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में योगी ने लिखा कि प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन प्रदान करें।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में श्री धामी ने लिखा कि बाबा केदारनाथ आपको सुदीर्घ,आरोग्यपूर्ण एवं सुखद जीवन प्रदान करें।

राजिम पुन्नी मेला को कुंभ बनाना सनातन परंपरा का अपमान

रायपुर। भाजपा सरकार द्वारा राजिम पुन्नी मेला को कुंभ बनाना सनातन परंपरा और छत्तीसगढ़ की पुरातन संस्कृति दोनो का अपमान है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सनातन धर्म और हिन्दु पुराणों परंपरा के अनुसार कुंभ केवल 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही प्रत्येक स्थानों में 12 वर्षो में लगता है। केवल प्रयाग में हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता, इसके अलावा कही पर भी होने वाले धार्मिक मेले को कुंभ नाम दिया जाना सनातन धर्म और हिन्दु धर्म की पौराणिक मान्यताओ का मखौल उड़ाना है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजिम पुन्नी मेला भगवान राजिव लोचन की धर्म भूमि पैरी, सोंढुर और महानदी के संगम स्थल राजिम में 100 वर्षो से अधिक समय से लगता है। यह छत्तीसगढ़ की वैभवशाली संस्कृति का प्रतीक है। पुन्नी मेला के रूप में छत्तीसगढ़ के जनमन में इसका अपना महत्व और श्रद्धा है। अपनी राजनीति चमकाने के लिये भाजपा सरकार इसके महत्व को कम करने की कोशिश कर रही है। आखिर भाजपा को छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा तीज त्यौहार से इतनी नफरत क्यों है? प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा तीज त्यौहार खान-पान बोली भाषा को देश और दुनिया में एक नई पहचान दिलाई हैं।

मोदी के वादों का हिसाब न मांग ले इसलिये शाह बुद्धिजीवी सम्मेलन में नहीं जा रहे

रायपुर। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे है। अमित शाह ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में से बुद्धिजीवी सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि अमित शाह को इस बात का भय सता रहा कि बुद्धिजीवी लोग मोदी के 10 सालों के वायदों का हिसाब मांगेंगे तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है, इसीलिये वे बुद्धिजीवी सम्मेलन में नहीं जा रहे। मोदी ने 10 सालों के कार्यकाल में अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी और भाजपा देश की जनता से वायदा किया था- 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। हर के खाते में 15 लाख आयेंगे। 35 रू. लीटर में डीजल, पेट्रोल देंगे। हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करेंगे। कृषि ऊपजों का समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना किया जायेगा। विदेश से कालाधन लाया जायेगा। 100 स्मार्ट सिटी बनाया जायेगा। सभी सांसद एक गांव को गोद लेकर उसको आधुनिक बनायेंगे। 2022 तक देश के हर आवासहीन का अपना मकान होगा।

कृषि विवि में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की रणनीति का मसौदा तैयार

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र से नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु रणनीति तैयार करने के लिए आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु के पूर्व कुलपति डॉ राजेंद्र प्रसाद थे और अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल ने की। कार्यशाला के दौरान कृषि विश्वविद्यालय में नवीन शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया तथा इसके क्रियान्वयन हेतु रणनीति का मसौदा तैयार किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों के रूप में डॉ. एस. सुधाकर, प्राध्यापक तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, डॉ. के. गायकवाड़ प्राध्यापक, एन.आई.पी.बी., नई दिल्ली, डॉ. एस.के. दास, अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भुवनेश्वर, डॉ. एम. यासीन, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय सीहोर तथा डॉ. प्रमोद के. पाण्डेय, प्राध्यापक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (संयुक्त राज्य अमेरिका) शामिल हुए। कार्यशाला में कुलपति डॉ. चंदेल ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणि वर्ष से नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने हेतु हर संभव प्रयास किये जाएंगे।

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

गरियाबंद। जिले के छुरा थाना में खौफनाक हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी माधव गोड़ को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि मृतक करण कुंजाम के बाड़ी में लगे फसल को आरोपी माधव के जानवर नुकसान पहुंचा रहे थे. जिसको लेकर वह जानवरों को बांधने की समझाइश दिया. इससे नाराज आरोपी ने टंगिया से हमला कर करण का सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर को जंगल की ओर ले गया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने छुरा थाना के हत्या मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने फैसला सुनाते हुए आरोपी माधो राम उर्फ माधव गोड़ उम्र 36 वर्ष को आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी भगवानी राम कुंजाम ने छुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 12 जुलाई 2021 को शाम लगभग 4 बजे वह अपने घर में था.उसी समय पड़ोस में रहने वाले आरोपी माधव गोड़ अपने हाथ में टंगिया लेकर आज जान से मार डालूंगा कहते हुए उसके पिता करण कुंजाम के घर में घुसा और पिता पर ताबड़तोड़ टंगिया से हमला कर रहा था. तब वह बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपी उसे भी जान से मारने की धमकी दिया. जिससे वह डरकर घर से बाहर निकल गया और घटना के बारे में अपनी पत्नी, पुत्र और गांव के लोगों को बताया. वहीं कुछ देर बाद आरोपी माधव गोड़ उसके पिता का कटा हुआ सिर और टंगिया लेकर जंगल की ओर चला गया.

वित्त मंत्री चौधरी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नवीन राशनकार्ड का किया वितरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री एवं जांजगीर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जांजगीर जिले की महिलाओं को नवीन राशनकार्ड का वितरण किया।

जिले के पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निशक्तजन राशनकार्ड के द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा है। बुधवार को प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा जांजगीर जिले में श्रीमती सविता सारथी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, श्रीमती सीमा सारथी, श्रीमती मीना तिवारी तथा श्रीमती कंतराबाई को नवीन राशन कार्ड का वितरण किया गया। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो का नवीनीकरण किया जा रहा है। जिसकी अंतिम तारीख 25 फरवरी 2024 है। इसमें कम से कम एक सदस्य का ई-केवायसी पूर्ण हो। अत्यधिक वृद्ध तथा शारीरिक रूप से निशक्त ऐसे हितग्राही जिनके लिए नामिनी नियुक्त हैं, उन्हें इस प्रावधान से छूट होगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के ऐसे नागरिक पलायन या अन्य किसी कारणवश राज्य से बाहर हैं, उनको राशनकार्ड नवीनीकरण कार्य के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। राशन कार्डधारियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए राशन कार्ड का नवीनीकरण खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप्प से हितग्राही स्वयं अपने मोबाइल में अथवा उचित मूल्य दुकानों में संधारित टैबलेट अथवा दुकान संचालक के पंजीकृत एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर आवेदन कर सकता है। आवेदक स्वयं राशन कार्ड नवीनीकरण कर सकता है। इस अवसर पर जांजगीर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राही उपस्थित थे।

लोस चुनाव की तैयारियां शुरूः छग-उड़ीसा अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक संपन्न

कानून व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों पर रोक और एन्टी नक्सल अभियानों पर हुई चर्चा

रायपुर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। आज संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग और रायपुर के पुलिस महानिरीक्षक श्री अमरेश मिश्रा की मौजूदगी में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सीमावर्ती राज्य उड़ीसा के अधिकारियों के साथ अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों को रोकने और माओवाद प्रभावित क्षेत्र में संयुक्त अभियानों पर चर्चा की गई। बैठक में रायपुर संभाग के महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी जिलों तथा उड़ीसा राज्य के कोरापुट, कालाहाण्डी, बलांगीर, मलकानगीरी, नवरंगपुर, बरगड़, नुआपाड़ा जिलों के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षकों सहित संबलपुर रेंज के आईजी और संभागायुक्त भी शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलाने और सप्लाई नेटवर्क को रोकने के लिए प्रभावी कार्य करने पर जोर दिया। रायपुर संभागायुक्त डॉ. अलंग ने बेहतर आपसी ताल-मेल के साथ आगामी लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी स्तर, पुलिस थाना स्तर, जिला स्तर पर भी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सूचनाओं के तेजी से आदान-प्रदान पर बल देते हुए वॉट्सएप्प ग्रुप बनाने की बात कही।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.